गरवी गुजरात

PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 063
दि. 02.07.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

व्हाट्सएप के नए यूज़रनेम फीचर पर सरकार की पैनी नज़र, साइबर सुरक्षा और फर्जी पहचान के खतरे को लेकर शुरु होगी समीक्षा

नई दिल्ली। दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप का प्रस्तावित यूजरनेम फीचर लॉन्च से पहले ही केंद्र सरकार की निगरानी में आ गया है। सरकार इस नए फीचर के सुरक्षा, गोपनीयता और कानूनी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा करने की तैयारी में है। अधिकारियों को आशंका है कि यदि पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना यह सुविधा शुरू की गई तो साइबर अपराधियों, ऑनलाइन ठगों और फर्जी पहचान बनाकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोहों के लिए यह नया माध्यम बन सकती है। यही कारण है कि सरकार ने इस फीचर को केवल तकनीकी सुविधा के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और डिजिटल विश्वास से जुड़े महत्वपूर्ण विषय के रूप में देखना शुरू कर दिया है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), दूरसंचार विभाग (DoT) तथा साइबर सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञ इस फीचर के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं। सरकार यह समझना चाहती है कि यदि उपयोगकर्ता केवल यूजरनेम के माध्यम से संवाद कर सकेंगे और मोबाइल नंबर सार्वजनिक रूप से साझा नहीं होगा, तो इसका साइबर अपराध, डिजिटल पहचान और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जांच प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

व्हाट्सएप का नया यूजरनेम फीचर उपयोगकर्ताओं को अपने मोबाइल नंबर की बजाय एक विशिष्ट यूजरनेम के माध्यम से अन्य लोगों से जुड़ने की सुविधा देने की दिशा में विकसित किया जा रहा है। इस व्यवस्था का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता बढ़ाना बताया जा रहा है, ताकि वे अपना निजी मोबाइल नंबर साझा किए बिना भी बातचीत कर सकें। इसी तरह की सुविधा पहले से टेलीग्राम और सिग्नल जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। हालांकि भारत सरकार का मानना है कि देश में करोड़ों उपयोगकर्ताओं और तेजी से बढ़ते डिजिटल लेनदेन को देखते हुए इस तरह की सुविधा के जोखिम भी उतने ही बड़े हो सकते हैं।

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि मोबाइल नंबर की बजाय केवल यूजरनेम के आधार पर पहचान बनने से अपराधियों के लिए किसी बैंक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, कंपनी प्रतिनिधि या परिचित व्यक्ति के नाम से मिलते-जुलते यूजरनेम बनाकर लोगों को भ्रमित करना आसान हो सकता है। फर्जी प्रोफाइल बनाकर निवेश, नौकरी, डिजिटल भुगतान, लोन, केवाईसी अपडेट और अन्य ऑनलाइन सेवाओं के नाम पर ठगी की घटनाएं बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ वर्षों में भारत में डिजिटल फ्रॉड के मामलों में तेजी आई है और साइबर अपराधी लगातार नए तरीके अपनाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में सरकार किसी भी नई तकनीकी सुविधा के संभावित दुष्प्रभावों का पहले से आकलन करना चाहती है।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह प्रस्तावित फीचर भारत के मौजूदा दूरसंचार और डिजिटल सुरक्षा नियमों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान व्यवस्था के तहत व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक खाते का एक सत्यापित मोबाइल नंबर से जुड़ा होना आवश्यक है। मोबाइल नंबर की यह व्यवस्था जांच एजेंसियों को आवश्यक परिस्थितियों में उपयोगकर्ताओं की पहचान स्थापित करने में सहायता करती है। यदि यूजरनेम आधारित संवाद प्रणाली अधिक प्रमुख हो जाती है, तो यह सुनिश्चित करना होगा कि सत्यापित मोबाइल नंबर की अनिवार्यता और कानूनी जवाबदेही किसी भी स्थिति में कमजोर न पड़े।

दूरसंचार विभाग द्वारा लागू किए गए टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स, 2024 का उद्देश्य डिजिटल धोखाधड़ी, सिम कार्ड के दुरुपयोग और साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। इन नियमों के तहत सिम आधारित पहचान और सत्यापन व्यवस्था को मजबूत बनाया गया है। सरकार यह मूल्यांकन कर रही है कि यूजरनेम आधारित संचार कहीं इन सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता को प्रभावित तो नहीं करेगा।

सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार जल्द ही व्हाट्सएप की मूल कंपनी मेटा से इस प्रस्तावित फीचर को लेकर विस्तृत जानकारी मांग सकती है। सरकार यह जानना चाहती है कि फर्जी यूजरनेम रोकने, किसी प्रतिष्ठित संस्था या व्यक्ति की पहचान का दुरुपयोग रोकने तथा शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए कंपनी ने कौन-कौन से सुरक्षा उपाय प्रस्तावित किए हैं। आवश्यकता पड़ने पर सरकार कंपनी को अतिरिक्त सुरक्षा प्रावधान लागू करने के निर्देश भी दे सकती है। सरकार का रुख स्पष्ट है कि यदि किसी नए डिजिटल फीचर के कारण साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी या राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जोखिम बढ़ते हैं तो संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही भी तय की जाएगी। केवल नई सुविधा उपलब्ध करा देना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक होगा कि उसका दुरुपयोग न्यूनतम हो और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहे।

विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता जितनी बढ़ती है, उतनी ही उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। भारत में व्हाट्सएप करोड़ों लोगों के दैनिक संचार, डिजिटल भुगतान, व्यापारिक गतिविधियों और सरकारी सेवाओं तक पहुंच का प्रमुख माध्यम बन चुका है। ऐसे में किसी भी नए फीचर का प्रभाव केवल व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसका असर पूरे डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ सकता है। हाल के वर्षों में साइबर अपराधियों ने फर्जी कॉल, फिशिंग लिंक, निवेश घोटाले, डिजिटल अरेस्ट, केवाईसी अपडेट, क्यूरियर स्कैम और बैंकिंग धोखाधड़ी जैसे अनेक तरीकों से लोगों को निशाना बनाया है। अधिकांश मामलों में अपराधी पहले विश्वास पैदा करते हैं और फिर आर्थिक ठगी को अंजाम देते हैं। यदि यूजरनेम आधारित पहचान में पर्याप्त सत्यापन व्यवस्था नहीं होगी तो ऐसे अपराधों की जांच और रोकथाम दोनों अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं।

सरकार का कहना है कि डिजिटल नवाचार का स्वागत किया जाएगा, लेकिन किसी भी नई तकनीक की कीमत नागरिकों की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों से समझौता करके नहीं चुकाई जा सकती। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप के प्रस्तावित यूजरनेम फीचर की विस्तृत तकनीकी और कानूनी समीक्षा की जाएगी। यदि समीक्षा में यह पाया जाता है कि मौजूदा सुरक्षा उपाय पर्याप्त नहीं हैं, तो कंपनी को आवश्यक संशोधन करने होंगे। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है—भारत का डिजिटल इकोसिस्टम अधिक सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह बना रहे, ताकि तकनीकी प्रगति के साथ-साथ नागरिकों का विश्वास भी मजबूत बना रहे।

भारत-पाक रिश्तों में नई पहल की अपील, 117 प्रमुख हस्तियों ने मोदी और शहबाज शरीफ को लिखा संयुक्त पत्र

नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्षों से चले आ रहे तनावपूर्ण संबंधों के बीच दोनों देशों की 117 प्रतिष्ठित हस्तियों ने एक साझा पहल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को संयुक्त पत्र लिखकर संवाद, विश्वास बहाली और द्विपक्षीय रिश्तों को सामान्य बनाने की अपील की है। इस पत्र में दोनों सरकारों से आग्रह किया गया है कि लगातार बढ़ते अविश्वास और टकराव की राजनीति से आगे बढ़कर बातचीत का रास्ता अपनाया जाए, ताकि दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता और विकास का नया वातावरण तैयार हो सके। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में पूर्व राजनयिक, सेवानिवृत्त नौकरशाह, राजनीतिक नेता, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल हैं।

इस पहल का समन्वय 'सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस' के चेयरमैन ओ.पी. शाह ने किया। 30 जून को तैयार किए गए इस पत्र पर भारत की 61 और पाकिस्तान की 56 प्रमुख हस्तियों ने हस्ताक्षर किए। पत्र को नई दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों सरकारों तक औपचारिक रूप से पहुंचाया गया है। हस्ताक्षरकर्ताओं का कहना है कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव का

सबसे अधिक असर आम नागरिकों, व्यापार, शिक्षा, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और क्षेत्रीय विकास पर पड़ा है। उनका मानना है कि संवाद की प्रक्रिया दोबारा शुरू करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

भारतीय पक्ष से पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती, राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा सहित अनेक पूर्व अधिकारी, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। पाकिस्तान की ओर से पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी सहित कई पूर्व राजनयिक, शिक्षाविद और सार्वजनिक जीवन से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों ने इस पहल का समर्थन किया है।

पत्र में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी देश हैं, इसलिए दोनों के बीच स्थायी शांति केवल द्विपक्षीय संवाद और आपसी विश्वास से ही संभव है। हस्ताक्षरकर्ताओं ने जोर देकर कहा है कि युद्ध, सैन्य तनाव और लगातार बढ़ती कटुता किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इसके विपरीत, बातचीत और कूटनीतिक संपर्क ही ऐसे माध्यम हैं, जिनसे जटिल मुद्दों पर भी समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। पत्र में दोनों सरकारों से सबसे पहले एक-दूसरे की राजधानियों में उच्चायुक्तों की पुनर्नियुक्ति करने का आग्रह किया गया है। वर्ष 2019 के बाद से दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध सीमित स्तर पर चल रहे हैं। हस्ताक्षरकर्ताओं का मानना है कि पूर्ण राजनयिक प्रतिनिधित्व बहाल होने से संवाद की प्रक्रिया को नई गति मिलेगी और आपसी गलतफहमियों को दूर करने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा सामान्य वीजा सेवाएं दोबारा शुरू करने की भी मांग की गई है। पत्र में कहा गया है कि विभाजन के बाद भी दोनों देशों के करोड़ों लोगों के पारिवारिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध आज भी कायम हैं। वीजा प्रक्रिया आसान होने से परिवारों का मिलना-जुलना बढ़ेगा, व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग मजबूत होगा तथा दोनों देशों के नागरिकों के बीच विश्वास का वातावरण बनेगा। हस्ताक्षरकर्ताओं ने भारत और पाकिस्तान के बीच लंबित सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर व्यापक एवं निरंतर वार्ता फिर से शुरू करने का सुझाव भी दिया है। पत्र में विशेष रूप से वर्ष 2004 से 2007 के बीच दोनों देशों के बीच चले संवाद और उस दौरान तैयार किए गए विभिन्न सहमति ढांचों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि उन प्रयासों को आधार बनाकर आगे की बातचीत की जा सकती है। जम्मू-कश्मीर सहित सभी संवेदनशील मुद्दों पर शांतिपूर्ण और कूटनीतिक माध्यमों से चर्चा जारी रखने पर भी बल दिया गया है। पत्र में सुरक्षा संबंधी चिंताओं को भी स्वीकार किया गया है। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा है कि दोनों देशों की अपनी-अपनी वैध सुरक्षा आवश्यकताएं हैं, लेकिन इसके बावजूद सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव कम करने और सैन्य तैनाती में चरणबद्ध कमी लाने जैसे विश्वास बहाली के उपायों पर विचार किया जाना चाहिए।

चार्जशीट की प्रति न मिलने से नहीं मिलेगा डिफॉल्ट जमानत का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट की कानूनी स्थिति

नई दिल्ली। डिफॉल्ट जमानत के अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल आरोप-पत्र (चार्जशीट) की प्रति आरोपी को उपलब्ध नहीं कराए जाने के आधार पर डिफॉल्ट जमानत नहीं दी जा सकती। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि जांच एजेंसी कानून में निर्धारित समय सीमा के भीतर विधिवत चार्जशीट दाखिल कर देती है, तो आरोपी का डिफॉल्ट जमानत का वैधानिक अधिकार स्वतः समाप्त हो जाता है। चार्जशीट की प्रति उपलब्ध कराने जैसी प्रक्रिया में किसी प्रकार की कमी या देरी को डिफॉल्ट जमानत का आधार नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें एक आरोपी की डिफॉल्ट जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। आरोपी ने अदालत में दलील दी थी कि यद्यपि जांच एजेंसी ने निर्धारित अवधि के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी थी, लेकिन उसकी प्रति उसे उपलब्ध नहीं कराई गई। इसलिए उसे डिफॉल्ट जमानत का लाभ मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि कानून का उद्देश्य समयबद्ध जांच सुनिश्चित करना है, न कि प्रक्रिया संबंधी हर त्रुटि को डिफॉल्ट जमानत का आधार बनाना।

पीठ ने अपने फैसले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 के प्रावधानों की विस्तार से व्याख्या करते हुए कहा कि धारा 193(3) के तहत यदि निर्धारित प्रारूप में समय सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है, तो जांच एजेंसी ने अपनी वैधानिक जिम्मेदारी पूरी कर दी मानी जाएगी। इसके बाद आरोपी डिफॉल्ट जमानत का दावा नहीं कर सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि धारा 193(8) के तहत चार्जशीट की अतिरिक्त प्रतियां दाखिल नहीं किए जाने या उनकी आपूर्ति में हुई कमी से स्वयं चार्जशीट अमान्य नहीं हो जाती।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले लागू दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और वर्तमान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) दोनों में डिफॉल्ट जमानत का मूल सिद्धांत समान है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जांच एजेंसियां किसी आरोपी को अनिश्चितकाल तक हिरासत में रखकर जांच लंबित न रखें। इसलिए यदि 60 या 90 दिनों की निर्धारित अवधि—जैसा कि अपराध की प्रकृति के अनुसार कानून में तय है—के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती, तभी आरोपी को डिफॉल्ट जमानत का वैधानिक अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन एक बार समय सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद यह अधिकार समाप्त हो जाता है।

अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट शब्दों में कहा कि बीएनएसएस की धारा 193(8) के अनुपालन में किसी प्रकार की कमी को धारा 187(3) के तहत मिलने वाले डिफॉल्ट जमानत के अधिकार के समान नहीं माना जा सकता। दोनों प्रावधानों का उद्देश्य और कानूनी प्रभाव अलग-अलग हैं। इसलिए चार्जशीट की प्रति उपलब्ध कराने में हुई त्रुटि या विलंब को जांच पूरी न होने के बराबर नहीं माना जा सकता।

यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक बड़े साइबर धोखाधड़ी प्रकरण से जुड़ा है। जांच एजेंसी के अनुसार लगभग 3.81 करोड़ रुपये की साइबर ठगी को अंजाम देने वाले अपराधियों ने आधुनिक डिजिटल तकनीकों, फर्जी पहचान, जाली दस्तावेजों और विभिन्न बैंक खातों का उपयोग कर लोगों से धोखाधड़ी की। जांच के दौरान यह भी आरोप सामने आया कि कुछ बैंक अधिकारियों ने संदिग्ध लेन-देन और खातों के संचालन में कथित रूप से अपराधियों की सहायता की थी, जिसके बाद मामले की जांच का दायरा और विस्तृत किया गया।

गिरफ्तार आरोपी ने पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में डिफॉल्ट जमानत की मांग करते हुए कहा था कि उसे चार्जशीट की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई, इसलिए उसकी हिरासत कानून के अनुरूप नहीं मानी जा सकती। हाईकोर्ट ने यह दलील अस्वीकार करते हुए कहा था कि समय सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल होने के बाद डिफॉल्ट जमानत का अधिकार समाप्त हो चुका है। इसी आदेश को चुनौती देते हुए आरोपी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निष्कर्ष से सहमति जताते हुए कहा कि निचली अदालत ने कानून की सही व्याख्या की है। शीर्ष अदालत ने माना कि चार्जशीट दाखिल करने और उसकी प्रति उपलब्ध कराने की प्रक्रिया अलग-अलग कानूनी पहलू हैं। यदि प्रति उपलब्ध कराने में कोई त्रुटि है, तो उसके लिए आरोपी अन्य कानूनी उपाय अपना सकता है, लेकिन इसे डिफॉल्ट जमानत का आधार नहीं बनाया जा सकता। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भविष्य में डिफॉल्ट जमानत से जुड़े मामलों के लिए महत्वपूर्ण नजीर साबित होगा।

सीवर-सेप्टिक टैंकों की खतरनाक मैनुअल सफाई कब बंद होगी? श्रमिकों की जान अभी भी खतरे में है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। आजकल छोटे-बड़े सभी काम आधुनिक उपकरणों की सहायता से किए जाते हैं। लेकिन नालियों की सफाई के लिए पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल अभी भी खतरनाक है। परिणामस्वरूप, सेप्टिक टैंक और नालियों की सफाई के दौरान होने वाली मौतें आम बात हो गई हैं।

पिछले सप्ताह, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुंडाडा इलाके में भी इसी तरह की एक घटना सामने आई। जहां एक कारखाने के सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय जहरीली गैस के कारण तीन मजदूरों की जान चली गई। इस घटना ने एक बार फिर सुरक्षा नियमों की अनदेखी को उजागर किया है। खबरों के अनुसार, मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा उपाय के सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए भेजा गया था।

जिसके कारण यह त्रासदी हुई।

यह तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि दिल्ली समेत पूरे देश में अदालत के निर्देशों का गंभीरता से पालन नहीं किया जा रहा है। इस मुद्दे पर एक विस्तृत आदेश में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सेप्टिक टैंकों और सीवरों की मैन्युअल सफाई पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। हालांकि, हमारे गुजरात समेत कई राज्यों में समय-समय पर ऐसी दुर्घटनाओं की खबरें आती रहती हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है कि सुरक्षा नियमों का पालन करने के सख्त निर्देशों के बावजूद, श्रमिकों को बिना किसी सावधानी के सीवरों और सेप्टिक टैंकों में उतारा जा रहा है।

कर्मचारियों को जहरीली गैसों के बीच भेजने से पहले ऑक्सीजन की आपूर्ति की जांच या उसकी शुद्धता का आकलन करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। इसी कारण, ऐसे हादसों में जान गंवाने वाले सफाई कर्मचारियों के परिवारों को मुआवज़ा देने के संबंध में भी कोई स्पष्ट नीति नहीं है। वास्तव में, केवल कागज़ पर नियम बनाने से व्यवस्था में सुधार नहीं आता। यह आवश्यक है कि इन्हें ज़मीनी स्तर पर सख्ती से लागू किया जाए और ऐसी शर्मनाक और कलंकित घटनाओं को हमेशा के लिए समाप्त किया जाए।

राजस्थान में सामूहिक बलात्कार के आरोप में 13 वर्षीय लड़की गिरफ्तार, 10 आरोपी गिरफ्तार, विवाद का केंद्र बना

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। एक तरफ जहां पूरे देश में "बेटी को बचाओ, बेटी को शिक्षित करो" का नारा गूंज रहा है, वहीं दूसरी तरफ 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसके जीवन को बर्बाद करने की एक शर्मनाक घटना सामने आई है।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, राजस्थान के श्री गंगानगर में आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली 13 वर्षीय छात्रा के साथ चार दिनों के भीतर लगभग एक दर्जन लोगों ने यौन उत्पीड़न किया। शनिवार को सामने

आए इस मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जांच तेज कर दी गई है।

इस संबंध में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में कहा गया है कि आरोपियों ने दुर्व्यवहार के दौरान लड़की को शराब पिलाई। लड़की को चार होटलों में प्रताड़ित किया गया। लड़की के परिवार ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने उसे 22 जून को जॉय इन होटल में पाया, जो इन आरोपियों का शिकार था।

संपादकीय

सरलता की जरूरत

तकनीक ने मानव जीवन की रफ्तार को अभूतपूर्व गति दी है। सुबह की चाय के डिजिटल भुगतान से लेकर हवाई टिकट और बैंकिंग तक, सब कुछ अब एक छोटी-सी स्क्रीन पर सिमट गया है। युवाओं के लिए यह सुविधा और अवसर का नया संसार है, लेकिन हमारे बुजुर्गों के लिए यही दुनिया कई बार उलझन, असुरक्षा और निर्भरता का कारण बन जाती है। अपनों से जुड़े रहने की खुशी और हर काम के डिजिटल होने की मजबूरी के बीच पुरानी पीढ़ी जिस संघर्ष से गुजर रही है, वह आज की एक बड़ी विडंबना बन गई है।

स्मार्टफोन अब केवल युवाओं का उपकरण नहीं रहा। दादा-दादी वीडियो कॉल पर दूर बैठे अपने पोते-पोतियों को देखकर भावुक हो उठते हैं। व्हाट्सएप पर परिवार से जुड़े रहना, पुराने मित्रों को खोजना और यूट्यूब पर भजन सुनना उनके अकेलेपन को काफी हद तक कम करता है। लेकिन यही तकनीक कई बार उनके लिए परेशानी का कारण भी बन जाती है। स्क्रीन पर दर्जनों एप, लगातार आने वाले संदेश, अचानक बदली हुई सेटिंग या किसी जरूरी फाइल के मिट जाने का डर उन्हें हमेशा असहज बनाए रखता है। छोटी-सी तकनीकी चूक भी उनका आत्मविश्वास डगमगा देती है। कई बुजुर्ग इस डर से स्मार्टफोन का सीमित उपयोग करते हैं और हर नए डिजिटल काम के लिए परिवार के किसी सदस्य का इंतजार करते हैं। उनकी आत्मनिर्भरता भी प्रभावित होती है।

सबसे गंभीर चिंता साइबर ठगी का बढ़ता खतरा है। डिजिटल दुनिया की सीमित समझ का फायदा उठाकर अपराधी बुजुर्गों को सबसे आसान निशाना बना रहे हैं। फर्जी बैंक अधिकारी, पुलिसकर्मी या सरकारी कर्मचारी बनकर फोन करना अब आम बात हो गई है। 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे नए साइबर अपराधों में ठग वीडियो कॉल के जरिए कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर वरिष्ठ नागरिकों से लाखों-करोड़ों रुपये ठग लेते हैं। केवाईसी अपडेट, पेंशन बंद होने या बैंक खाते के सत्यापन के नाम पर ओटीपी और बैंक विवरण हासिल कर जीवनभर की जमा-पूंजी साफ कर दी जाती है। आर्थिक नुकसान उन्हें गहरा मानसिक आघात भी पहुंचाता है, जिससे कई बुजुर्ग अवसाद और असुरक्षा के शिकार हो जाते हैं। कई मामलों में ठगी के बाद वे खुद को दोषी मानने लगते हैं, परिवार के सामने अपनी बात रखने से हिचकिचाते हैं। स्थिति आर्थिक ही नहीं, भावनात्मक संकट भी पैदा करती है। मगर वे इस डिजिटल व्यवस्था से दूर नहीं रह सकते। पेंशन, बैंकिंग, बिजली-पानी के बिल, सरकारी योजनाएं और स्वास्थ्य सेवाएं लगातार ऑनलाइन होती जा रही हैं। पहले पेंशनभोगी बैंक जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करते थे। अब डिजिटल जीवन प्रमाण की प्रक्रिया में बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी है। बढ़ती उम्र के साथ उंगलियों के निशान धुंधले पड़ जाने से कई बार सत्यापन सफल नहीं हो पाता। ऐसे में उन्हें बार-बार सेवा केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बैंकिंग भी अब पासबुक से आगे बढ़कर पासवर्ड, ओटीपी और मोबाइल एप पर निर्भर हो गई है। एक पासवर्ड भूल जाने का मतलब कई बार अपने ही पैसे के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाना है। रेलवे टिकट, अस्पताल में पंजीकरण, गैस बुकिंग, बीमा, पेंशन और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने जैसी अनेक सेवाओं में भी डिजिटल माध्यम प्रमुख हो चुका है। ऐसे में तकनीक से दूरी का अब विकल्प नहीं रह गया है। डिजिटल बदलाव का एक सामाजिक पहलू भी है। संयुक्त परिवारों के टूटने और युवाओं के रोजगार हेतु बाहर जाने से बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं। ऐसे में मोबाइल और इंटरनेट अनिवार्य जरूरत बन गए हैं। जब उनके सामने तकनीकी समस्या आती है, तब अकेलापन व असहायता का एहसास गहरा हो जाता है। जरूरी है कि डिजिटल साक्षरता को केवल तकनीकी प्रशिक्षण नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा के रूप में भी देखें। निस्संदेह, तकनीक दौर में चुनौती यह है कि विकास समावेशी हो। डिजिटल सेवाओं का डिज़ाइन वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप बनाया जाए। बैंकिंग व सरकारी एप अधिक सरल हों, बड़े वित्तीय लेनदेन में अतिरिक्त मानवीय सत्यापन की व्यवस्था हो तथा साइबर सुरक्षा को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाएं। बैंक, डाकघर, पंचायतें, स्वयंसेवी संस्थाएं और स्थानीय प्रशासन समय-समय पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल प्रशिक्षण शिविर लगाएं। इससे आत्मविश्वास बढ़ने संग, वे तकनीक का सुरक्षित उपयोग कर सकेंगे। डिजिटल साक्षरता गांव व मोहल्ले तक पहुंचे। जिन माता-पिता और दादा-दादी ने कभी हमारी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज उन्हें डिजिटल दुनिया में हमारा सहारा चाहिए। उनकी हर शंका पर झल्लाने के बजाय धैर्य से समझाना होगा कि कोई बैंक या पुलिस अधिकारी फोन पर ओटीपी नहीं मांगता और न ही वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी होती है। तकनीक की सफलता तभी है, जब वह हर पीढ़ी को साथ लेकर चले। आधुनिकता का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब हमारे बुजुर्ग भी डिजिटल दुनिया में सम्मान, आत्मविश्वास और सुरक्षा के साथ जी सकें।

पानी पाकिस्तान का बंद हुआ है, मगर गला यहां के 'शांति दूतों' का क्यों सूख रहा है?

> "देखा जाये तो दशकों तक भारतीयों का खून बहाने वाला पाकिस्तान अब पानी की कमी होने पर कांप रहा है और वहां के नेता गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सिंधु पाकिस्तान की जीवनरेखा है और भारत पानी को हथियार बना रहा है।

पहलगाम हमले के बाद भारत ने जिस दृढ़ता के साथ पाकिस्तान को उसकी असली जगह दिखानी शुरू की है, उससे इस्लामाबाद की सत्ता, सेना और वहां के कथित लोकतांत्रिक चेहरे बुरी तरह बौखला गए हैं। सिंधु जल संधि को स्थगित करने के भारत के फैसले ने पाकिस्तान की नसों में ऐसा डर भर दिया है कि वहां के नेता लगातार धमकियां दे रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रो रहे हैं और दुनिया को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ने उनके अस्तित्व पर हमला कर दिया है।देखा जाये तो दशकों तक भारतीयों का खून बहाने वाला पाकिस्तान अब पानी की कमी होने पर कांप रहा है और वहां के नेता गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सिंधु पाकिस्तान की जीवनरेखा है और भारत पानी को हथियार बना रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान अपने पानी, अपनी संप्रभुता और अपने भविष्य की रक्षा करेगा। पाकिस्तान के जलवायु मंत्री मुसद्दिक मलिक ने तो यहां तक कह दिया कि जो हाथ उनके पानी को छुएंगे, उन्हें काट दिया जाएगा। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने भी भारत पर पानी रोकने का आरोप लगाते हुए आक्रामक बयान दिए। पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री इशाक डार ने दुनिया को डराने की कोशिश की कि यदि सिंधु जल संधि नहीं बची तो द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की पूरी विश्व व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी।

लेकिन पाकिस्तान के इन आंसुओं के पीछे छिपा सच पूरी दुनिया जानती है। पहलगाम में 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले आतंकवादी कहां से आए थे? जम्मू-कश्मीर में दशकों से आतंकवाद को कौन पालता रहा है? भारत के सैनिकों और नागरिकों का खून बहाने के लिए हथियार, प्रशिक्षण और धन कौन देता रहा है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सही कहा था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करके यह स्पष्ट कर दिया कि अब नई दिल्ली पुरानी नीति पर नहीं चलेगी। यदि पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति बनाए रखेगा तो उसे हर मोर्चे पर कीमत चुकानी होगी। भारत ने पश्चिमी नदियों पर अपने अधिकार वाले जल के उपयोग को तेज करने का फैसला किया है। यह कोई युद्ध नहीं, बल्कि अपने अधिकारों का प्रयोग है।

साथ ही सबसे बड़ा सवाल उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जो भारत में बैठकर पाकिस्तान से वार्ता की मांग कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि एक सौ से अधिक तथाकथित बुद्धिजीवियों, नेताओं और सामाजिक हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाहबाज शरीफ को पत्र लिखकर बातचीत बहाल करने, वीजा सेवाएं शुरू करने, दूतावास सामान्य करने और यहां तक कि कश्मीर पर फिर से बातचीत करने की मांग की है। इस पत्र पर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मीरवाइज उमर फारूक और कुछ अन्य भारतीय हस्तियों के हस्ताक्षर भी हैं।

इन लोगों से देश पूछना चाहता है कि आखिर पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों है? जो देश भारत में आतंकवादी भेजता है, हमारे नागरिकों की हत्या करवाता है, सीमा पार से गोलियां चलाता है, उसी देश के लिए इनके दिल में इतनी बेचैनी क्यों उमड़ती है? भारत ने जब पाकिस्तान का पानी रोकने की दिशा में कदम उठाया तो प्यास पाकिस्तान को लगी, लेकिन गला यहां बैठे तथाकथित शांति दूतों का सूखने लगा। आखिर क्यों? क्या इन लोगों को भारत की सुरक्षा से ज्यादा चिंता पाकिस्तान की खेती और उसकी बिजली व्यवस्था की है?

ये लोग कहते हैं कि वार्ता ही समाधान है। लेकिन देश जानना चाहता है कि आखिर कितनी वार्ताएं हो चुकी हैं? लाहौर बस यात्रा से लेकर आगरा शिखर वार्ता तक और उफा से लेकर शरम अल शेख तक भारत ने हर बार शांति का हाथ बढ़ाया। बदले में मिला क्या? कारगिल, संसद हमला, मुंबई हमला, उरी, पुलवामा और अब पहलगाम। पाकिस्तान हर बार वार्ता की मेज पर मुस्कुराता है और पीठ पीछे आतंकियों को भेजता है।

आज जब भारत पहली बार कठोर नीति पर डटा है तो देश के भीतर बैठे कुछ लोग बेचैन हो उठे हैं। उन्हें आतंकवाद पर गुस्सा नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान का पानी रुकने पर दर्द होने लगता है। उन्हें भारत के शहीदों की चिंता कम और इस्लामाबाद की परेशानी ज्यादा दिखाई देती है। यह वही मानसिकता है जिसने दशकों तक भारत को कमजोर नीति में बांध कर रखा।

सच यह है कि सिंधु जल संधि का सबसे ज्यादा लाभ पाकिस्तान ने उठाया। भारत ने वर्षों तक उदारता दिखाई, जबकि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता रहा। अब जब नई दिल्ली ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंक और व्यापार, आतंक और वार्ता, आतंक और पानी साथ साथ नहीं चल सकते, तब पाकिस्तान दुनिया भर में सहानुभूति जुटाने निकला है। लेकिन दुनिया भी समझ रही है कि समस्या की जड़ कहां है।

पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि धमकियों से भारत डरने वाला नहीं है। पानी को लेकर युद्ध जैसे बयान देने वाले पहले अपने घर की हालत देखें। वहां की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, जनता महंगाई से त्रस्त है और सेना तथा सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए भारत विरोध का सहारा ले रही हैं।

देखा जाये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान नीति ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नया भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि अपने हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम भी उठाएगा। आतंकवाद को पालने वालों को अब हर क्षेत्र में जवाब मिलेगा। पाकिस्तान यदि वास्तव में शांति चाहता है तो उसे पहले आतंकवाद की फैक्टरी बंद करनी होगी। जब तक उसकी धरती से भारत विरोधी आतंक जारी रहेगा, तब तक कोई भी वार्ता केवल छलावा मानी जाएगी। बहरहाल, भारत की जनता अब भ्रम में नहीं है। देश समझ चुका है कि शांति की सबसे पहली शर्त सुरक्षा है। और जो लोग पाकिस्तान के लिए आंसू बहा रहे हैं, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि भारत की सहनशीलता को कमजोरी समझने की भूल अब कोई नहीं कर सकता। नया भारत अपने सैनिकों के खून का हिसाब भी लेगा और अपने पानी का अधिकार भी बचाएगा।

प्रेरणा

**मनुष्य की सबसे लंबी यात्रा: चांद से नहीं, इंसान से इंसान तक

कहा जाता है कि सभ्यता का सबसे बड़ा परिचय उसकी उपलब्धियों से मिलता है। आज जब दुनिया विज्ञान और तकनीक की नई ऊंचाइयों को छू रही है, तब यह दावा भी बड़े गर्व से किया जाता है कि मानव इतिहास अपने सबसे विकसित दौर में है। इंसान ने समुद्र की अथाह गहराइयों को नापा, आसमान की सीमाओं को लांघा, चांद पर अपने कदमों के निशान छोड़े और अब मंगल ग्रह पर स्थायी बस्तियां बसाने के सपने देख रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ऐसी मशीनें तैयार कर रही है जो इंसानों की तरह सोचने, समझने और संवाद करने लगी हैं। चिकित्सा विज्ञान असंभव मानी जाने वाली बीमारियों का इलाज खोज रहा है। संचार इतना तेज हो गया है कि दुनिया के किसी भी कोने की खबर कुछ ही सेकंड में हर हाथ में मौजूद मोबाइल तक पहुंच जाती है। लेकिन इन सारी उपलब्धियों के बीच एक सवाल आज भी उतना ही बड़ा है जितना सदियों पहले था—क्या इंसान वास्तव में इंसान तक पहुंच पाया है? यदि इस प्रश्न का उत्तर दुनिया की वर्तमान स्थिति को देखकर दिया जाए, तो शायद उत्तर संतोषजनक नहीं होगा। सुबह का अखबार उठाइए, कहीं युद्ध की खबर है। टीवी चलाइए तो किसी सीमा पर तनाव बढ़ने की चर्चा है। इंटरनेट खोलिए तो किसी नए संघर्ष, किसी नई मिसाइल, किसी नए सैन्य अभियान या किसी नए प्रतिबंध की सुर्खियां दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया का नक्शा देशों की सीमाओं से कम और संघर्षों की रेखाओं से अधिक पहचाना जाने लगा है। विज्ञान ने दूरियां घटा दीं, लेकिन दिलों की दूरियां कम नहीं कर सका। विडंबना यह है कि जिन लोगों का इन युद्धों से कोई सीधा संबंध नहीं होता, सबसे अधिक असर उन्हीं पर पड़ता है। कोई किसान खेत में हल चला रहा होता है, कोई मजदूर रोज की मजदूरी के लिए घर से निकलता है, कोई शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा होता है और कोई दुकानदार अपने ग्राहकों का इंतजार कर रहा होता है। इनमें से किसी ने युद्ध की योजना नहीं बनाई, किसी ने मिसाइल नहीं चलाई, किसी ने किसी देश के खिलाफ बयान नहीं दिया, फिर भी युद्ध का सबसे बड़ा आर्थिक बोझ आखिरकार इन्हीं लोगों के कंधों पर आ गिरता है। एक दिन एक सामान्य ग्राहक किराने की दुकान पर पहुंचा और रोजमर्रा का सामान खरीदने लगा। उसने देखा कि आटा, दाल, तेल और गैस सिलेंडर के दाम फिर बढ़ गए हैं। उसने दुकानदार से पूछा, "भाई, हर महीने कीमतें क्यों बढ़ जाती हैं?" दुकानदार ने मुस्कराकर जवाब दिया, "दुनिया में तनाव बढ़ गया है।" ग्राहक ने आश्चर्य से कहा, "लेकिन तनाव तो हजारों किलोमीटर दूर है।" दुकानदार ने हंसते हुए कहा, "साहब, अब तनाव भी हवाई जहाज से चलता है, इसलिए बहुत जल्दी यहां पहुंच जाता है।" यह बात सुनकर हंसी भी आती है और सोचने पर मजबूर भी करती है। सच यही है कि आधुनिक दुनिया में युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहते। उनकी गूंज वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार, ऊर्जा, खाद्यान्न और आम आदमी की जेब तक पहुंच जाती है। कहीं बंदरगाह बंद होता है तो यहां बाजार में सामान महंगा हो जाता है। कहीं तेल उत्पादन प्रभावित होता है तो हजारों किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लग जाती हैं। कहीं व्यापारिक मार्ग बाधित होता है तो छोटे दुकानदार तक उसका असर महसूस करने लगते हैं। दुनिया जितनी जुड़ी है, उतनी ही संवेदनशील भी हो गई है। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की भूमिका भी अब कई बार उस मोहल्ला समिति जैसी प्रतीत होती है जो हर विवाद के बाद बैठक तो बुलाती है, चिंता भी व्यक्त करती है, शांति की अपील भी करती है, लेकिन झगड़ा समाप्त नहीं करा पाती। प्रस्ताव पारित होते हैं, बयान जारी होते हैं, प्रतिनिधिमंडल भेजे जाते हैं, मगर अगले ही दिन किसी नए क्षेत्र से धुएं और धमाकों की खबर आने लगती है। ऐसा लगता है कि शांति की भाषा सब बोलते हैं, लेकिन उसे सुनने वाले बहुत कम रह गए हैं। दुनिया की बड़ी शक्तियों का व्यवहार भी कम विरोधाभासी नहीं है। एक ओर वे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर शांति, सहयोग और मानवता की बातें करती हैं, वहीं दूसरी ओर हथियारों के उत्पादन और व्यापार में नए-नए रिकॉर्ड बनाती हैं। शांति सम्मेलन में कबूतर उड़ाए जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद रक्षा सौदों की घोषणाएं होने लगती हैं। यह दृश्य कई बार ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई व्यक्ति पहले बीमारी फैलाए और फिर उसी बीमारी की दवा बेचने लगे। युद्ध जितना विनाश लाता है, उतना ही बड़ा कारोबार भी खड़ा करता है। शायद यही कारण है कि दुनिया में शांति की सबसे अधिक चर्चा होती है, लेकिन हथियारों का बाजार भी लगातार बढ़ता रहता है। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि हर युद्ध गलत नहीं होता। कभी-कभी राष्ट्र की सुरक्षा, सीमाओं की रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए संघर्ष आवश्यक हो जाता है। यह बात अपनी जगह सही हो सकती है। किसी भी देश को अपनी संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा का अधिकार है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब युद्ध समाधान की जगह प्रतिष्ठा, शक्ति प्रदर्शन या राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का माध्यम बन जाता है। तब उसकी कीमत सैनिकों के साथ-साथ उन करोड़ों निर्दोष लोगों को भी चुकानी पड़ती है जिनका उस संघर्ष से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता।

युद्ध केवल इमारतें नहीं गिराता, वह विश्वास भी तोड़ देता है। वह केवल सड़कें और पुल नहीं नष्ट करता, बल्कि पीढ़ियों के सपनों को भी मलबे में बदल देता है। किसी शहर पर गिरा एक बम केवल दीवारों को नहीं तोड़ता, वह बच्चों की मुस्कान, बुजुर्गों की सुरक्षा, परिवारों की खुशियां और भविष्य की उम्मीदों को भी घायल कर देता है। युद्ध समाप्त होने के बाद भी उसके घाव वर्षों तक समाज की स्मृतियों में जीवित रहते हैं।

विज्ञान ने मनुष्य को अद्भुत शक्ति दी है। वही शक्ति जीवन बचाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है और विनाश फैलाने के लिए भी। परमाणु ऊर्जा से बिजली भी बनाई जा सकती है और परमाणु बम भी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा और चिकित्सा को बेहतर बना सकती है, लेकिन यदि उसका उपयोग विनाशकारी हथियारों में हो तो वही तकनीक मानवता के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए असली प्रश्न तकनीक का नहीं, उसे उपयोग करने वाले मनुष्य के विवेक का है।

सभ्यता की महानता इस बात से नहीं मापी जाएगी कि उसने कितने ग्रहों तक पहुंच बनाई, बल्कि इस बात से मापी जाएगी कि उसने पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के बीच कितना विश्वास, कितना सम्मान और कितनी शांति स्थापित की। यदि विज्ञान की ऊंचाइयों के साथ मानवता की गहराई नहीं बढ़ी, तो सारी प्रगति अधूरी रह जाएगी। चांद पर झंडा गाड़ देना बड़ी उपलब्धि है, लेकिन किसी भूखे बच्चे की थाली भर देना उससे कहीं बड़ी मानवता है। अंतरिक्ष में जीवन खोजने से पहले यदि धरती पर जीवन को सुरक्षित और सम्मानपूर्ण बनाया जाए, तो शायद विज्ञान का उद्देश्य भी अधिक सार्थक होगा।

Bangladesh से बजा चाइनीज अलार्म भारत के लिए कितना बड़ा खतरा? अब 'मुनरो डॉक्ट्रिन' लागू करने का टाइम आ गया

बचपन में कछुए और खरगोश की रेस वाली कहानी तो हम सबने सुनी है? रफ्तार के घमंड में चूर खरगोश पेड़ की छांव में सोता रह गया और कछुआ धीरे-धीरे बाजी मार ले गया। आज दक्षिण एशिया के समंदर में भारत और चीन के बीच ठीक यही कहानी दोहराई जा रही है, और इसका सबसे ताजा व खतरनाक गवाह बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट बना है। कहानी की शुरुआत में बाजी भारत के हाथ में थी। नई दिल्ली ने बीजिंग को सीधी शिकस्त देकर इस रणनीतिक पोर्ट के अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट अपने नाम किया था। लगा कि रेस जीत ली गई है, लेकिन कछुए की चाल चल रहे चीन ने हार नहीं मानी, वो चुपचाप अपनी गोटियां फिट करता रहा। देखते ही देखते 10 साल बीत गए! ढाका बीजिंग से हाथ मिला चुका था और जो डील भारत की मुट्ठी में थी, वह चीन की झोली में जा गिरी थी। तो बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट हाथ से जाना भारत के लिए कितना बड़ा झटका है? क्या चीन एक और छोर से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। अब भारत क्या कर सकता है? इन तमाम सवालों का एमआरआई स्कैन करेंगे। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए मोंगला पोर्ट एक लाइफ लाइन की तरह है। समुद्र से कटे होने की वजह से इन राज्यों तक सामान पहुंचाना हमेशा एक चुनौती रही है। मोंगला पोर्ट के जरिए सामान समुद्री रास्ते से पहुंचाया जा सकता है। इससे भारत के 22 किमी चौड़े चिकन नेक पर भी निर्भरता कम होगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घटेगी और देश के बाक़ी हिस्सों से पूर्वोत्तर भारत का आर्थिक संपर्क बेहतर हो जाता। 2009 से 2024 तक 15 साल बांग्लादेश पर आवामी लीग के नेता शेख हसीना का शासन रहा। इन 15 सालों में शेख हसीना को भारत का सबसे भरोसेमंद पड़ोसी नेता माना जाता था। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा। इस दौर में कनेक्टिविटी समझौते हुए और बांग्लादेश ने भारत को अपने पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचने के लिए अपनी जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत भी दी। बदले पर भारत ने भी शेख हसीना सरकार का खुलकर साथ दिया, निवेश किया। कोरोना जैसे कठिन समय में मदद पहुंचाई और कूटनीतिक समर्थन भी दिया। इसी माहौल में 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक अहम एमओयू पर दस्तखत हुए। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस समझौते के तहत बांग्लादेश ने अपने दो बड़े बंदरगाह चटगांव और मोंगला का इस्तेमाल भारत को अपने पूर्वोत्तर राज्यों तक सामान पहुंचाने के लिए करने की इजाजत दी। दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में इसे एक बड़ी सफलता माना गया। इसी योजना के तहत मोंगला पोर्ट के पास 110 एकड़ जमीन भी भारत को दी गई ताकि वहां एक स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन बनाया जा सके। प्लान था कि भारत वहां फैक्ट्रियां लगाएगा, गोदाम बनाएगा और एक इंडस्ट्रियल हब तैयार करेगा। इससे भारतीय कंपनियों को फायदा होता। बांग्लादेश में रोजगार पैदा होता और दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते और मजबूत होते। साथ ही उस इलाके में भारत की मौजूदगी भी बढ़ाता। जहां चीन भी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। 2018 में भारत ने इस प्रोजेक्ट के लिए हीरानं ग्रुप को डेवलपर चुना। बाद में उसकी सहयोगी कंपनी एविटा कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड ने मार्च 2022 में बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी बेजा के साथ एक नया समझौता भी किया। डील पर डील होती रही, योजनाएं बनती रही लेकिन काम कभी शुरू भी नहीं हुआ। 2 साल की तय समय सीमा भी निकल गई लेकिन जमीन पर एक फावड़ा तक नहीं चला। फिर आया 204 जुलाई और अगस्त में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। शुरुआत सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन से हुई। उस समय सरकार नौकरियों का करीब 1/3 हिस्सा 1971 के मुक्ति संग्राम के सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित कर रही थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल शेख हसीना अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए कर रही हैं। लेकिन देखते ही देखते बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और लंबे समय से चले आ रहे सत्तावादी शासन से नाराज हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। आखिरकार 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई। तब से लेकर अब तक भारत में ही वह रह रही हैं। इसके बाद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के लीडरशिप में अंतरिम सरकार बांग्लादेश में बनी। यहीं से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में बड़ा मोड़ आया।

पिछले 15 साल में जो भरोसा और साझेदारी बनी थी उसमें दरार पड़नी शुरू हो गई। दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव बढ़ा। व्यापार को लेकर जवाबी कदम उठाए गए एक दूसरे पर और नेताओं के बयान भी पहले से ज्यादा तल्ख हो गए। इसी दौरान बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ भी अपने रिश्ते तेजी से बढ़ाने शुरू कर दिए। 1971 के बाद पहली बार ढाका और इस्लामाबाद के बीच सीधी कारगो शिपिंग सेवा और डायरेक्ट फ्लाइट्स का ऐलान किया गया। इन सारी डेवलपमेंट्स पर चीन की पैनी नजर थी। इस बीच मार्च 2025 में मोहम्मद यूनुस बीजिंग पहुंचे। बस तभी चीन ने अपना तुरुब का इक्का चला। उसने दो बड़े ऐलान किए। पहला मूंगला पोर्ट को एडवांस बनाने के लिए $40 करोड़ देने का वादा। दूसरा एक नए चीनी इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक ज़ोन के लिए $35 करोड़ के निवेश का ऐलान। यानी चीन सिर्फ दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। बल्कि बड़े पैमाने पर निवेश करने के लिए तैयार था। चीन इससे पहले बांग्लादेश के चटगांव नौसैनिक बंदरगाह के निकट पेकुआ पनडुब्बी अड्डा बनाने का काम भी कर रहा है। इससे बांग्लादेश की नौसेना भी पूरी तरह चीन की मुट्ठी में होगी। इसी बहाने बांग्लादेश के समुद्र तटों पर, जो भारत के समुद्री इलाके में ही हैं, चीन ने अपनी पनडुब्बियों और युद्धपोतों को भी तैनात करने की सुविधा हासिल कर ली है। सीमाओं के पास चीन अपने खुफिया एजेंटों व सैनिकों को तैनात कर सकता है। CPEC की तरह ही चीन ने बांग्लादेश से चीन-म्यांमार-बांग्लादेश आर्थिक गलियारा (CMEC) में शामिल होने को कहा है। पाकिस्तान के ग्वादर, बांग्लादेश के चटगांव और श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन म्यांमार से होकर गुजरने वाला प्रस्तावित राजमार्ग बना लेगा तो उसके लिए यह सामरिक तौर पर उपयोगी होगा।

अभियान

आस्था की रसोई या विज्ञान की पहेली? पुरी के महाप्रसाद का अनोखा रहस्य

भारत की सांस्कृतिक विरासत में कुछ ऐसे धार्मिक स्थल हैं, जिनकी पहचान केवल पूजा-अर्चना या ऐतिहासिक महत्व तक सीमित नहीं है, बल्कि वहां से जुड़ी परंपराएं भी उन्हें दुनिया भर में विशिष्ट बनाती हैं। ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर ऐसा ही एक अद्भुत तीर्थ है, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यह मंदिर विश्वप्रसिद्ध रथ यात्रा, विशाल स्थापत्य और भगवान जगन्नाथ की अनूठी परंपराओं के लिए जाना जाता है। लेकिन इन सबके बीच मंदिर की रसोई और वहां तैयार होने वाला महाप्रसाद भी उतना ही प्रसिद्ध है। इस रसोई की सबसे रोचक बात यह है कि यहां आज भी सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनाया जाता है। इन्हें एक-दूसरे के ऊपर रखकर लकड़ी की आग पर पकाया जाता है और लोकमान्यता के अनुसार सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पक जाता है। यही परंपरा वर्षों से श्रद्धालुओं, पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए जिज्ञासा का विषय बनी हुई है। भगवान जगन्नाथ मंदिर भारत के चार प्रमुख धामों में शामिल है और इसकी धार्मिक प्रतिष्ठा अत्यंत उच्च मानी जाती है। इतिहासकारों के अनुसार वर्तमान मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के महान शासक अनंतवर्मन चोडगंग देव ने कराया था। तब से लेकर आज तक मंदिर की पूजा-पद्धति, सेवाएं और महाप्रसाद बनाने की परंपरा लगभग अपरिवर्तित बनी हुई है। समय के साथ दुनिया में तकनीक ने अभूतपूर्व प्रगति की, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की रसोई आज भी उसी पारंपरिक व्यवस्था के साथ संचालित होती है, जो सदियों पहले स्थापित की गई थी। यही कारण है कि इसे केवल धार्मिक व्यवस्था नहीं, बल्कि जीवित सांस्कृतिक धरोहर भी माना जाता है। मंदिर की रसोई को विश्व की सबसे बड़ी पारंपरिक मंदिर रसोइयों में स्थान प्राप्त है। यह विशाल परिसर अनेक कक्षों और सैकड़ों पारंपरिक चूल्हों से सुसज्जित है। प्रतिदिन यहां हजारों श्रद्धालुओं के लिए भोजन तैयार किया जाता है। लगभग 600 रसोइए और 400 से अधिक सहयोगी सेवक इस सेवा में लगे रहते हैं। इन परिवारों की कई पीढ़ियां वर्षों से इसी सेवा को अपना धार्मिक दायित्व मानकर निभा रही हैं। भोजन बनाना उनके लिए केवल पाक-कला नहीं, बल्कि भगवान की सेवा का एक पवित्र माध्यम है। यही कारण है कि प्रत्येक प्रक्रिया अत्यंत अनुशासन, शुद्धता और निर्धारित धार्मिक नियमों के अनुसार पूरी की जाती है। इस रसोई की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां भोजन आज भी मिट्टी के बर्तनों में ही बनाया जाता है। चावल, दाल, सब्जियां, खिचड़ी, खीर, पिठा, मीठे व्यंजन और अन्य पारंपरिक ओड़िया पकवान नए मिट्टी के पात्रों में पकाए जाते हैं। प्रत्येक दिन नए बर्तनों का उपयोग किया जाता है। लकड़ी की आग पर धीरे-धीरे पकने वाला यह भोजन अपने विशिष्ट स्वाद और सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। आधुनिक रसोई उपकरणों का यहां लगभग कोई उपयोग नहीं होता। यही परंपरा महाप्रसाद को सामान्य भोजन से अलग पहचान देती है। सबसे अधिक चर्चा उस विधि की होती है जिसमें कई मिट्टी के बर्तनों को एक-दूसरे के ऊपर रखकर भोजन पकाया जाता है। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि आग के सबसे निकट रखा गया बर्तन पहले गर्म होगा, लेकिन जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी लोकमान्यता इसके विपरीत है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पक जाता है और उसके बाद नीचे रखे बर्तनों का भोजन तैयार होता है। इस विश्वास ने वर्षों से लोगों के मन में आश्चर्य और जिज्ञासा दोनों को जन्म दिया है।

मंदिर की धार्मिक मान्यता के अनुसार यह भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी की दिव्य कृपा का परिणाम है। विश्वास किया जाता है कि मंदिर की रसोई में माता लक्ष्मी स्वयं अदृश्य रूप से भोजन बनाने की व्यवस्था का संचालन करती हैं। इसी कारण यहां बनने वाला प्रत्येक व्यंजन विशेष पवित्र माना जाता है। श्रद्धालुओं के लिए यह किसी वैज्ञानिक सिद्धांत का विषय नहीं, बल्कि आस्था का प्रमाण है। उनके अनुसार जहां ईश्वर की कृपा होती है, वहां सामान्य नियम भी असाधारण रूप धारण कर लेते हैं। दूसरी ओर वैज्ञानिक इस परंपरा को ऊष्मा के संचरण, भाप के प्रवाह और मिट्टी के बर्तनों की संरचना के आधार पर समझाने का प्रयास करते हैं। उनका मानना है कि लकड़ी की आग से उठने वाली गर्म भाप ऊपर की ओर जाती है और विशेष परिस्थितियों में ऊपरी बर्तनों तक अधिक ताप पहुंच सकता है। हालांकि इस विषय पर ऐसा कोई व्यापक वैज्ञानिक शोध उपलब्ध नहीं है जो इस प्रक्रिया को पूरी तरह प्रमाणित कर सके। इसलिए इसे आज भी एक रोचक लोकमान्यता और अध्ययन का विषय माना जाता है। आस्था और विज्ञान दोनों अपनी-अपनी दृष्टि से इसे समझने का प्रयास करते हैं। भगवान जगन्नाथ को प्रतिदिन 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित किया जाता है, जिसे छप्पन भोग कहा जाता है। इसमें चावल, दाल, खिचड़ी, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, दही, खीर, मालपुआ, पिठा, मीठे चावल, लड्डू और अनेक पारंपरिक व्यंजन शामिल होते हैं। प्रत्येक व्यंजन निश्चित समय और निर्धारित विधि के अनुसार तैयार किया जाता है। यहां भोजन का उद्देश्य केवल स्वाद प्रदान करना नहीं, बल्कि सात्विकता और धार्मिक परंपरा का पालन करना भी है। मसालों से लेकर पानी तक के उपयोग में निर्धारित नियमों का पालन किया जाता है।

महाप्रसाद बनने की प्रक्रिया भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सबसे पहले तैयार भोजन भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को अर्पित किया जाता है। इसके बाद यही भोग देवी विमला को समर्पित किया जाता है। धार्मिक परंपरा के अनुसार देवी विमला को अर्पण के पश्चात ही यह भोजन महाप्रसाद कहलाता है। इसके बाद इसे श्रद्धालुओं के बीच वितरित किया जाता है। हजारों लोग प्रतिदिन इस महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं और इसे भगवान का आशीर्वाद मानते हैं। महाप्रसाद की एक विशेषता सामाजिक समानता का संदेश भी है। यहां प्रसाद ग्रहण करते समय किसी व्यक्ति की जाति, वर्ग, भाषा, क्षेत्र या आर्थिक स्थिति का कोई महत्व नहीं होता। सभी श्रद्धालु एक साथ बैठकर भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह परंपरा भारतीय संस्कृति में सामाजिक समरसता और समानता की भावना को सशक्त रूप से प्रस्तुत करती है। सदियों पहले स्थापित यह व्यवस्था आज भी समाज को एकता और भाईचारे का संदेश देती है। मंदिर प्रशासन की व्यवस्था भी उल्लेखनीय है। प्रतिदिन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या का अनुमान लगाकर महाप्रसाद तैयार किया जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और न ही अत्यधिक मात्रा में बचता है। इसे भगवान की कृपा माना जाता है, जबकि प्रबंधन विशेषज्ञ इसे सदियों के अनुभव और सटीक व्यवस्था का परिणाम बताते हैं। यह व्यवस्था दुनिया भर के शोधकर्ताओं के लिए भी अध्ययन का विषय बनी हुई है। रथ यात्रा के दौरान इस रसोई का महत्व और बढ़ जाता है। लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति के बावजूद पारंपरिक व्यवस्था सुचारु रूप से चलती रहती है। इतने बड़े स्तर पर भोजन तैयार करना और उसे व्यवस्थित ढंग से वितरित करना अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण है। यही कारण है कि इतिहासकार, खाद्य विशेषज्ञ, संस्कृति के शोधकर्ता और प्रबंधन के विद्यार्थी भी इस रसोई की कार्यप्रणाली को समझने में रुचि लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर की रसोई केवल भोजन बनाने का स्थान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, सेवा, अनुशासन और सामूहिक श्रम का जीवंत प्रतीक है। यहां प्रत्येक व्यंजन श्रद्धा, समर्पण और धार्मिक विश्वास के साथ तैयार किया जाता है। महाप्रसाद केवल भोजन नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के बीच आध्यात्मिक संबंध का माध्यम माना जाता है। यही कारण है कि पुरी आने वाला लगभग प्रत्येक श्रद्धालु दर्शन के साथ महाप्रसाद ग्रहण करना भी अपनी यात्रा का अनिवार्य हिस्सा मानता है। आज जब दुनिया आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक उपलब्धियों पर गर्व कर रही है, तब भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर की यह प्राचीन रसोई लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। एक ही आग पर कई मिट्टी के बर्तनों में भोजन पकाने की परंपरा, महाप्रसाद की धार्मिक महिमा, सदियों से चले आ रहे नियम और उत्कृष्ट प्रबंधन इस स्थान को विशेष बनाते हैं। चाहे इसे आस्था का चमत्कार कहा जाए, पारंपरिक ज्ञान का उदाहरण या वैज्ञानिक जिज्ञासा का विषय, इतना निश्चित है कि जगन्नाथ मंदिर की रसोई भारत की उस समृद्ध विरासत का प्रतीक है, जहां विश्वास, संस्कृति, सेवा और अनुशासन मिलकर ऐसी परंपराओं को जन्म देते हैं, जो समय बीतने के बाद भी लोगों के मन में सम्मान और आश्चर्य दोनों बनाए रखती हैं।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmdabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

विकसित गुजरात@2047 के विजन को जमीनी स्तर पर लागू करने की दिशा में राज्य सरकार की एक निर्णायक और परिवर्तनकारी पहल

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में विकसित गुजरात 2047 कार्यान्वयन रोडमैप का अनावरण किया

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित गुजरात 2047 कार्यान्वयन रोडमैप राज्य की विकास यात्रा का एक निर्णायक पड़ाव है

▸▸ सभी के समन्वित और निष्ठापूर्ण प्रयासों से विकसित गुजरात का निर्माण अवश्य ही होगा

▸▸ गुजरात राज्य इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन (जीआरआईटी) और सामान्य प्रशासन विभाग के आयोजन प्रभाग द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए विकसित गुजरात 2047 कार्यान्वयन रोडमैप के अनावरण अवसर पर वित्त मंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों की प्रेरक उपस्थिति

▸▸ सरकार के पास संसाधनों या पैसों की कोई कमी नहीं है : अब केवल सच्ची निष्ठा, मजबूत निगरानी और समय पर समीक्षा की ही जरूरत : मुख्य सचिव श्री एम.के. दास

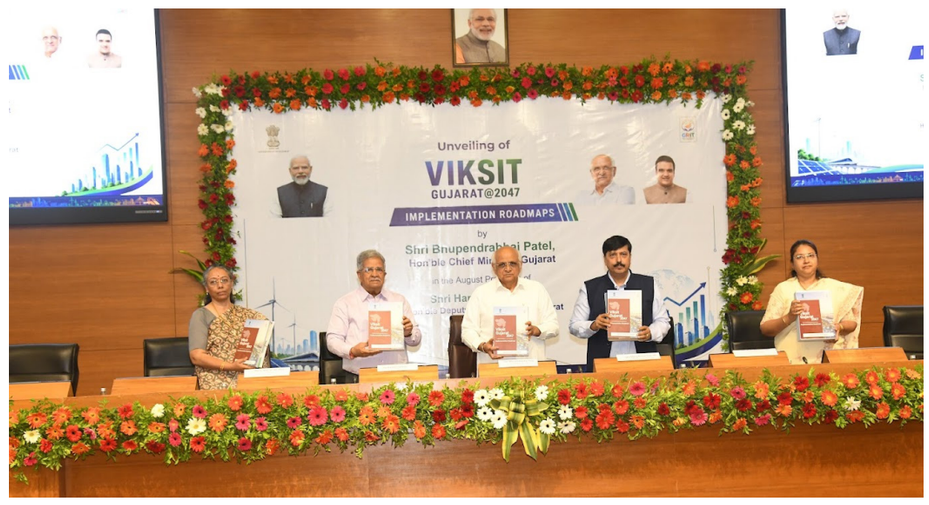

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने विकसित गुजरात @ 2047 कार्यान्वयन रोडमैप के अनावरण के जरिए विजन से ऑन ग्राउंड एक्जीक्यूशन (जमीनी स्तर पर लागू करना) की ओर राज्य सरकार की एक निर्णायक और परिवर्तनकारी पहल की है।

मुख्यमंत्री द्वारा बुधवार को गांधीनगर में जारी किया गया यह रोडमैप गुजरात राज्य इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन (जीआरआईटी-ग्रिट) और सामान्य प्रशासन विभाग के आयोजन प्रभाग की ओर से संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई, मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्य सचिव श्री एम.के. दास और मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया सहित कई वरिष्ठ सचिव मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप तैयार किए गए विकसित गुजरात 2047 कार्यान्वयन रोडमैप को राज्य की विकास यात्रा का एक निर्णायक पड़ाव बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' का मंत्र दिया है, जिसमें उनकी मंशा राज्यों की भी सक्रिय भागीदारी से समावेशी विकास सुनिश्चित करना है।

उन्होंने साफ कहा कि रोडमैप यह स्पष्ट करता है कि क्या करने की आवश्यकता है, किसे करना है और किस समयसीमा में करना है, जिससे एक केंद्रित (फोकस्ड) और जवाबदेह शासन सुनिश्चित होता है। मुख्यमंत्री ने लक्ष्य के बजाय परिणामों पर जोर देते हुए कहा कि यह कार्यान्वयन रोडमैप अंततः नागरिकों के लिए बेहतर आजीविका, मजबूत बुनियादी ढांचा, समावेशी और टिकाऊ विकास के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में उपयोगी सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें शासन में गुणवत्ता की प्रधानमंत्री की हिमायत को जीआरआईटी-ग्रिट की स्थापना और उसके द्वारा तैयार किए गए दीर्घकालिक रणनीतिक विजन वाले रोडमैप के कार्यान्वयन के जरिए चरितार्थ करना है, जिसका लक्ष्य गुजरात को प्रतिस्पर्धी, समावेशी, टिकाऊ और टेक्नोलॉजी-ड्रिवन स्टेट के रूप में स्थापित करना है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आम आदमी की खुशहाली और उसके आर्थिक आधार को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए 'अनिंग वेल, लिविंग वेल' यानी बेहतर कमाई, बेहतर जीवन की जो अवधारणा दी है, उसे पूरा करने में ग्रिट के इस रोडमैप का कार्यान्वयन पथप्रदर्शक बनेगा।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि हमने विकसित गुजरात 2047 कार्यान्वयन रोडमैप में जो माइक्रो प्लानिंग की है, उसे कार्ययोजना के माध्यम से लागू करने तथा समन्वित और निष्ठापूर्ण साझा प्रयासों से विकसित गुजरात अवश्य ही बनेगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 12 वर्षों के सुशासन में विकास के जो दृष्टिकोण अपनाए हैं, उसे आगे बढ़ाने से राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा का वातावरण बना है। गुजरात ने विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी रहने का जो संकल्प किया है, उसे बनाए रखने के लिए निरंतर कार्यरत रहना होगा।

इस उद्देश्य के लिए, मुख्यमंत्री ने हमेशा बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और 'चलता है' वाली मानसिकता को दूर करके 100 फीसदी शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्यों की बात को केंद्र में रखकर गुणवत्ता से समझौता नहीं करने की सीख भी दी।

मुख्य सचिव श्री एम.के. दास ने कहा कि आज भारत अभाव से प्रभाव की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए के लिए विकसित गुजरात का रोडमैप तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो असंभव न हों, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़े। सौभाग्य से गुजरात सरकार के पास संसाधन या बजट-धन की कोई कमी नहीं है, इसलिए अब केवल सच्ची निष्ठा, मजबूत निगरानी और समय पर समीक्षा की ही जरूरत है।

मुख्य सचिव ने आगे कहा कि विकास की इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक कलेक्टरों और जिला विकास अधिकारियों (डीडीओ) तक, सभी अधिकारियों को और भी सक्रिय होना पड़ेगा। यदि किसी विभाग को अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए कोई वित्तीय सहायता, नीति में बदलाव या नए निर्णयों की जरूरत हो, तो सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, बंदरगाह और परिवहन सहित सभी क्षेत्रों में केपीआई के अनुसार संतुलित विकास ही हमारी प्राथमिकता है।

जीआरआईटी की सीईओ सुश्री एस. अपर्णा ने 'विकसित गुजरात @2047 कार्यान्वयन रोडमैप' पर विस्तृत प्रेजेंटेशन देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में जनवरी, 2024 में विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया था, जिसमें राज्य के सभी 26 विभागों के संयुक्त प्रयासों से वर्ष 2047 तक गुजरात का सकल घरेलू उत्पादन (जीएसडीपी) 3.5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस रोडमैप में लिविंग वेल और अर्निंग वेल के मंत्र को साकार करने के लिए मुख्य 11 थीम (विषय), 120 मैक्रो गोल (व्यापक लक्ष्य) तथा 55 की थ्रस्ट एरिया (प्रमुख फोकस क्षेत्र) निर्धारित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि विकसित गुजरात @2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रत्येक विभाग द्वारा तय किए गए लक्ष्यों के आधार पर ही यह रोडमैप तैयार किया गया है। जिसमें राज्य के 26 विभागों के लिए लगभग 900 स्टेप्स निर्धारित किए गए हैं। विकसित गुजरात @2047 डैशबोर्ड में शिक्षा, कृषि, पर्यटन और जलापूर्ति विभाग में मौजूदा स्थिति और भविष्य के आयोजन के बारे में रोडमैप को साकार करने के लिए किए जाने वाले कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

सामान्य प्रशासन विभाग की सचिव (आयोजन) श्री आद्रा अग्रवाल ने स्वागत भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने 'विकसित भारत@2047' की परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की है। इसी विजन के अनुरूप गुजरात सरकार ने भी वर्ष 2047 तक वैश्विक स्तर पर समृद्ध, प्रतिस्पर्धी, सर्वसमावेशी, टिकाऊ और इनोवेशन-आधारित राज्य बनने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

उन्होंने आगे कहा कि इन विकास कार्यों की सटीक समीक्षा के लिए गांधीनगर स्थित 'ग्रिट' कार्यालय में एक अत्याधुनिक 'स्ट्रैटेजी रूम' तैयार किया गया है, जिसमें डिजिटल डैशबोर्ड के माध्यम से प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा।

कार्यक्रम के अंतर में 'ग्रिट' की जॉइंट सीईओ श्री स्तुति चारण ने आभार व्यक्त किया।

मानसून के दौरान महेसाणा-तारंगा हिल रेलखंड पर तीन रेलवे अंडरपास अस्थायी रूप से रहेंगे बंद

यात्रियों एवं आम नागरिकों की सुरक्षा तथा सुरक्षित एवं सुचारु रेल परिचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अहमदाबाद मण्डल द्वारा महेसाणा–तारंगा हिल रेलखंड पर स्थित तीन रेलवे अंडरपास (RUB) को मानसून अवधि के दौरान भारी वर्षा होने की स्थिति में 10 जुलाई, 2026 से 30 सितम्बर, 2026 तक अस्थायी रूप से बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसका विवरण निम्नानुसार है—

रेलवे अंडरपास (RUB) संख्या 41A – वडनगर सिटी के समीप (केसिंपा खेतों का मार्ग विस्तार)

रेलवे अंडरपास (RUB) संख्या 16D – विसनगर सिटी के समीप (शेरडीनगर से कांसा विस्तार)

रेलवे अंडरपास (RUB) संख्या 22A – मस्तान नगर सोसायटी, वडनगर दरवाजा

अहमदाबाद मण्डल आम नागरिकों से अनुरोध करता है कि इस अवधि में रेलवे प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें तथा भारी वर्षा के दौरान इन रेलवे अंडरपासों का उपयोग करने से बचें।

बच्चों के स्वस्थ-सुरक्षित भविष्य की दिशा में गुजरात सरकार की अनूठी पहल, राज्य में 18 साल तक के हर बच्चे का बनेगा 'हेल्थ पासपोर्ट'

▸▸ 992 मोबाइल हेल्थ टीमों द्वारा हर साल 1.89 करोड़ बच्चों (0-18 वर्ष) का चेकअप कर तैयार किया जाएगा 'हेल्थ पासपोर्ट'

▸▸ जन्म से 18 साल तक की पूरी मेडिकल हिस्ट्री, बीमारियों (4D) की ट्रैकिंग और पोषण का स्तर अब एक ही डॉक्युमेंट में

▸▸ 5 साल तक व स्कूल न जाने वाले बच्चों का कार्ड PHC मेडिकल ऑफिसर, जबकि छात्रों का कार्ड स्कूल प्रिंसिपल करेंगे रिन्यू

वडोदरा, 01 जुलाई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर इस बात पर ज़ोर देते हैं कि एक 'स्वस्थ भारत' की मजबूत नींव, 'स्वस्थ बचपन' पर ही रखी जा सकती है। पीएम मोदी के इसी विजन को धरातल पर उतारते हुए और 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने की दिशा में, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार बच्चों व किशोर-किशोरियों की हेल्थकेयर सुविधाओं को और ज्यादा स्मार्ट, सस्टेनेबल और फैमिली एवं चाइल्ड फ्रेंडली बनाने के लिए 'हेल्थ पासपोर्ट' का कॉन्सेप्ट लेकर आई है। स्कूल हेल्थ - राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (SH-RBSK) के तहत अब गुजरात में जन्म से 18 साल तक के हर बच्चे का अपना एक हेल्थ पासपोर्ट होगा। यह सिर्फ कोई सामान्य हेल्थ कार्ड नहीं, बल्कि बच्चे की जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की पूरी स्वास्थ्य यात्रा का एक पक्का डॉक्युमेंट होगा। उल्लेखनीय है कि इस राज्यव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत 27 जून 2026 को केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की उपस्थिति में की गई है।

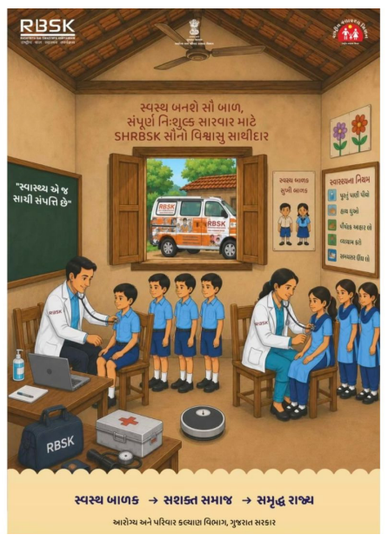

1.89 करोड़ बच्चों के पास होगा अपना 'हेल्थ पासपोर्ट', 992 मोबाइल टीमें करेंगी तैयार

गुजरात में SH-RBSK के तहत हर साल लगभग 1.89 करोड़ बच्चों का हेल्थ चेकअप 992 मोबाइल हेल्थ टीमों द्वारा किया जाता है। फिलहाल इन चेकअप्स का रिकॉर्ड डिजिटल पोर्टल पर तो मौजूद है, लेकिन माता-पिता या बच्चों के पास ऐसा कोई हैंडी डॉक्युमेंट नहीं होता, जिसे वे रेगुलर रूटीन चेकअप, इलाज या फॉलो-अप के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकें। प्रस्तावित 'हेल्थ पासपोर्ट' इसी कमी को दूर करेगा और बच्चों के मेडिकल रिकॉर्ड्स को एक सिस्टमैटिक और आसान फॉर्मैट में पेश करेगा।

आसान होगी हेल्थ पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया, स्क्रीनिंग स्थल पर ही मिलेगा पासपोर्ट, कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं

अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को बेहद सरल रखा गया है। बच्चों का 'हेल्थ पासपोर्ट' बनवाने के लिए माता-पिता को कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। SH-RBSK की मोबाइल हेल्थ टीमों द्वारा आंगनवाड़ी, स्कूल, मदरसा, गुरुकुल और स्पेशल स्कूलों में बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग और डिजिटल प्लैटफॉर्म पर डेटा एंट्री के बाद बच्चों को यह हेल्थ पासपोर्ट वहीं दे दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इसके रिन्यूअल की व्यवस्था भी स्पष्ट है। 5 साल तक के बच्चों या स्कूल न जाने वाले बच्चों के हेल्थ पासपोर्ट को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) के मेडिकल ऑफिसर (MO) द्वारा हर साल रिन्यू किया जाएगा। वहीं, स्कूली छात्रों के लिए यह जिम्मेदारी स्कूल के प्राचार्य निभाएँगे।

18 साल तक के बच्चों की पूरी हेल्थ हिस्ट्री का 'इन्टीग्रेटेड रिकॉर्ड' बनेगा गुजरात का 'हेल्थ पासपोर्ट'

यह हेल्थ पासपोर्ट हर बच्चे की पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री का एक मास्टर डॉक्युमेंट होगा। इसमें बच्चे की बेसिक डिटेल्स के साथ जन्म से 18 साल तक के उम्र-वार हेल्थ चेकअप का पूरा रिकॉर्ड दर्ज रहेगा। इसके अलावा, स्कूल हेल्थ-राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (SH-RBSK) के तहत फोकस की जाने वाली चार प्रमुख कैटेगरीज (4D) यानी जन्मजात डिफेक्ट्स, बीमारियां, न्यूट्रिशन की कमी और डेवलपमेंट में देरी या विकलांगता का पूरा अपडेट इसमें शामिल होगा। यही नहीं, बच्चे की शारीरिक-मानसिक वृद्धि व विकास, पोषण का स्तर, रेफरल सर्विसेज, पोषण और स्वास्थ्य से जुड़े टिप्स, लाइफस्टाइल एडवाइस और इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी इस पासपोर्ट का हिस्सा होंगे। आसान शब्दों में कहें तो परिवारों को बच्चे की सेहत से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी।

इस पहल की सबसे बड़ी यूएसपी इसका डिजिटल इंटीग्रेशन है। हेल्थ पासपोर्ट की फिजिकल कॉपी माता-पिता के पास ही सुरक्षित रहेगी, लेकिन इसे SH-RBSK डिजिटल पोर्टल के साथ पूरी तरह से सिंक किया जाएगा, जिससे डेटा मैनेजमेंट बिल्कुल सीमलेस रहेगा। अगर किसी वजह से फिजिकल हेल्थ पासपोर्ट खो जाता है या खराब हो जाता है, तो नया हेल्थ पासपोर्ट मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा। गुजरात सरकार द्वारा बच्चों के लिए लाए जा रहे इस 'हेल्थ पासपोर्ट' का मकसद सिर्फ मेडिकल फाइलें तैयार करना नहीं है, बल्कि माता-पिता को बच्चों के हेल्थ मैनेजमेंट में एक एक्टिव पार्टनर बनाना है। इससे बच्चों, पैरेंट्स और हेल्थकेयर सिस्टम के बीच एक मजबूत बॉन्ड बनेगा।

बारिश की फुहारों में भी निखरे दुल्हन का रूप, मानसून वेडिंग के लिए अपनाएं स्मार्ट ब्यूटी और स्टाइल टिप्स

मानसून का मौसम अपने साथ हरियाली, ठंडी हवाएं और रिमझिम फुहारों का ऐसा सुहाना एहसास लेकर आता है, जो किसी भी शादी को और अधिक यादगार बना देता है। बारिश की बूंदों के बीच सजा विवाह समारोह अपने आप में एक अलग ही रोमांस और खूबसूरती समेटे होता है। यही कारण है कि आजकल कई जोड़े मानसून वेडिंग को प्राथमिकता देने लगे हैं। हालांकि यह मौसम जितना खूबसूरत है, उतनी ही सावधानी भी मांगता है। उमस, बारिश, नमी और फिसलन जैसी परिस्थितियां दुल्हन के मेकअप, हेयरस्टाइल, पहनावे और पूरे लुक को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए यदि आपकी शादी बारिश के मौसम में होने वाली है, तो केवल सुंदर परिधान चुनना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मौसम के अनुरूप पूरी तैयारी करना भी उतना ही जरूरी है।

दुल्हन की खूबसूरती केवल शादी वाले दिन किए गए मेकअप से नहीं निखरती, बल्कि उसकी शुरुआत कई सप्ताह पहले से त्वचा और बालों की नियमित देखभाल से होती है। मानसून के दौरान वातावरण में बढ़ी हुई नमी के कारण त्वचा पर अतिरिक्त तेल, पसीना और धूल जमा होने लगती है, जिससे चेहरा बेजान और थका हुआ दिखाई दे सकता है। खासकर तैलीय और मिश्रित त्वचा वाली महिलाओं को इस मौसम में विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। नियमित क्लीनिंग, टोनिंग और हल्के ऑयल-फ्री मॉइस्चराइज़र का उपयोग त्वचा को संतुलित बनाए रखता है और मेकअप के लिए बेहतर आधार तैयार करता है।

बारिश के मौसम में सबसे महत्वपूर्ण बात है वाटरप्रूफ मेकअप का चयन। सामान्य मेकअप उत्पाद नमी, पसीने या बारिश की हल्की बूंदों के संपर्क में आते ही फैल सकते हैं, जिससे पूरा लुक बिगड़ सकता है। इसलिए वाटरप्रूफ फाउंडेशन, कंसीलर, मस्कारा, आईलाइनर और लिप कलर का उपयोग करना बेहतर रहता है। शादी से कुछ दिन पहले मेकअप ट्रायल अवश्य कर लेना चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि कौन-से उत्पाद आपकी त्वचा पर लंबे समय तक टिकते हैं और मौसम का प्रभाव कितना पड़ता है। यदि संभव हो तो ट्रायल के दौरान चेहरे पर हल्के पानी के छींटे डालकर भी उसकी टिकाऊ क्षमता की जांच की जा सकती है।

मॉनसून में मेकअप को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए ट्रांसलूसेंट पाउडर बेहद उपयोगी साबित होता है। यह अतिरिक्त नमी और तेल को सोखकर चेहरे को मैट फिनिश देता है तथा मेकअप को बहने से बचाता है। क्रीम आधारित ब्लश और आई शैडो की बजाय पाउडर आधारित उत्पाद अधिक उपयुक्त रहते हैं क्योंकि वे अधिक समय तक टिके रहते हैं और उमस में जल्दी खराब नहीं होते।

आंखों का मेकअप करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यदि काजल या आईलाइनर का उपयोग करना है तो केवल वाटरप्रूफ उत्पाद ही चुनें। सामान्य काजल बारिश या पसीने की वजह से फैल सकता है, जिससे आंखों के आसपास कालापन दिखाई देने लगता है। बहुत भारी या गहरे रंग का आई मेकअप करने के बजाय हल्का और प्राकृतिक लुक अधिक आकर्षक लगता है। इसी प्रकार बिंदी के लिए वाटरप्रूफ लिक्विड बिंदी या अच्छी गुणवत्ता वाली स्टिकर, कुंदन अथवा स्टोन वाली बिंदी बेहतर विकल्प हो सकती है, क्योंकि ये नमी में भी अपनी जगह पर बनी रहती हैं।

मानसून में हेयरस्टाइल का चुनाव भी सोच-समझकर करना चाहिए। इस मौसम में खुले बाल जल्दी फ्रिज़ी हो जाते हैं और उनकी चमक कम हो सकती है। इसलिए साफ-सुथरा बन, लो बन, ब्रेडेड बन, फिशटेल चोटी या स्टाइलिश पोनीटेल जैसे हेयरस्टाइल अधिक सुविधाजनक रहते हैं। हल्के फूलों या आकर्षक हेयर एक्सेसरीज़ के साथ इन्हें और खूबसूरत बनाया जा सकता है। यदि बालों में फ्रिज़ की समस्या रहती है तो शादी से पहले हेयर स्पा या डीप कंडीशनिंग करवाना लाभदायक रहता है। एंटी-फ्रिज़ सीरम का उपयोग भी बालों को व्यवस्थित बनाए रखने में मदद करता है। बारिश के मौसम में परिधान का चयन भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। बहुत भारी, मोटे या अत्यधिक कढ़ाई वाले वस्त्र न केवल वजन बढ़ाते हैं, बल्कि भीगने पर असुविधाजनक भी हो जाते हैं। ऑर्गेंजा, शिफॉन, जॉर्जेट, क्रेप, साटन और हल्के सिल्क जैसे फैब्रिक मानसून के लिए बेहतर माने जाते हैं। ये कपड़े अपेक्षाकृत हल्के होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं और लंबे समय तक पहनने में आरामदायक रहते हैं। यदि लहंगा पहन रही हैं तो उसकी लंबाई इतनी रखें कि वह जमीन पर अधिक न घिसटे, जिससे कीचड़ और गंदगी से बचाव हो सके। दुपट्टे की लंबाई भी व्यावहारिक रखनी चाहिए ताकि उसे संभालना आसान रहे।

आभूषणों का चयन भी मौसम को ध्यान में रखकर करना चाहिए। बहुत भारी गहनों की बजाय हल्के लेकिन आकर्षक आभूषण पहनना अधिक आरामदायक रहता है। हीरे, मोती, क्रिस्टल या कुंदन की हल्की कढ़ाई और ज्वेलरी मानसून में सुंदर भी लगती है और नमी का प्रभाव भी अपेक्षाकृत कम पड़ता है। फुटवियर का चुनाव अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि मानसून वेडिंग में यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि शादी खुले लॉन या गार्डन में हो रही हो तो ऊंची हील पहनना जोखिम भरा हो सकता है। कीचड़ या गीली घास पर चलने में फिसलने का खतरा बना रहता है। ऐसे में स्टाइलिश पंजाबी जूती, वेज हील्स या मजबूत ग्रिप वाले आरामदायक फुटवियर बेहतर विकल्प होते हैं। ये न केवल सुरक्षित रहते हैं बल्कि लंबे समय तक पहनने में भी सुविधा देते हैं।

दुल्हन के साथ-साथ शादी में शामिल होने वाले मेहमानों को भी मानसून के अनुरूप तैयारी करनी चाहिए। अपने साथ एक सुंदर छाता, हल्का स्टोल, अतिरिक्त रूमाल, ब्लॉटिंग पेपर, मिनी मेकअप किट और टिश्यू रखना उपयोगी रहता है। इससे अचानक बारिश या नमी की स्थिति में मेकअप और लुक को आसानी से ठीक किया जा सकता है। मानसून वेडिंग का सबसे बड़ा आकर्षण उसका प्राकृतिक सौंदर्य होता है। हरियाली, बादलों से ढका आसमान और बारिश की हल्की फुहारें शादी की तस्वीरों को भी बेहद खूबसूरत बना देती हैं। यदि थोड़ी-सी योजना, सही ब्यूटी प्रोडक्ट्स, उपयुक्त परिधान और मौसम के अनुरूप स्टाइलिंग अपनाई जाए तो बारिश का मौसम किसी भी दुल्हन के लिए परेशानी नहीं, बल्कि उसकी खूबसूरती को और भी यादगार बनाने वाला अवसर बन सकता है। सही तैयारी के साथ मानसून की शादी रोमांस, ताजगी, आकर्षण और यादगार पलों का ऐसा संगम बन जाती है, जिसे जीवनभर संजोकर रखा जा सकता है।

— शहनाज़ हुसैन
अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सौंदर्य विशेषज्ञ एवं हर्बल क्वीन

केन्द्र सरकार की रिपोर्ट में गुजरात देशभर में अग्रसर

प्रवक्ता मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी

▸▸ वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2023 में टीबी के नए मरीजों में 34 प्रतिशत तथा मृत्यु दर में 37 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी

▸▸ वर्ष 2025 में 'स्टेट्स विथ मोस्ट इम्प्रूवमेंट' श्रेणी में गुजरात पूरे देश में प्रथम

▸▸ देश में सबसे कम टीबी के मामले वाले राज्यों में गुजरात छठे तथा बड़े राज्यों में चौथा स्थान प्राप्त किया

▸▸ 'नि-क्षय पोषण योजना' अंतर्गत वर्ष 2025 के दौरान 1,05,238 टीबी मरीजों को 57.60 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता

▸▸ वर्ष 2025 में राज्य में 3,971 ग्राम पंचायतों ने 'टीबी मुक्त पंचायत' का दर्जा प्राप्त किया

गांधीनगर : कैबिनट बैठक के बाद प्रवक्ता मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने कहा कि भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2023 में गुजरात में टीबी के नए मरीजों की दर में 34 प्रतिशत तथा टीबी के कारण होने वाली मृत्यु दर में 37 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गुजरात ने वर्ष 2025 में 'स्टेट्स विथ मोस्ट इम्प्रूवमेंट' श्रेणी में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के महत्वाकांक्षी 'टीबी मुक्त भारत अभियान' अंतर्गत गुजरात राज्य द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों पर विस्तृत चर्चा की गई।

प्रवक्ता मंत्री ने इस संबंध में आगे कहा कि भारत सरकार की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 के दौरान गुजरात में टीबी के नए मरीजों की अनुमानित दर प्रति एक लाख आबादी पर 186 दर्ज की गई है। इसके आधार पर गुजरात ने देश में सबसे कम टीबी बोझ वाले राज्यों में छठा तथा बड़े राज्यों में चौथा स्थान प्राप्त किया है।

चालू वर्ष के कामकाज का विवरण देते हुए प्रवक्ता मंत्री ने कहा कि जनवरी से मई–2026 के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रो रेटा के अनुसार निर्धारित 58,333 के लक्ष्य के मुकाबले राज्य में 57,334 अर्थात 98.30 प्रतिशत टीबी मरीजों की पहचान कर उन्हें उपचार के अंतर्गत लिया गया। इनमें से 50,928 यानी 91 प्रतिशत मरीज अल्पावधि में ही रोगमुक्त हो गए।

इसके अतिरिक्त; भारत सरकार द्वारा 24 मार्च 2026 से प्रारंभ किए गए 'टीबी मुक्त भारत अभियान – 100 दिवस अभियान' अंतर्गत राज्य के 5,012 उच्च जोखिम वाले गांवों में घर-घर जाकर टीबी सर्विलांस किया गया।

उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान 23.38 लाख व्यक्तियों की टीबी स्क्रीनिंग, 15.04 लाख व्यक्तियों की एक्स-रे जांच, 5.05 लाख व्यक्तियों की सटीक एनएएटी जांच तथा 32,377 नए टीबी मरीजों का निदान कर उनका उपचार शुरू किया गया है।

प्रवक्ता मंत्री ने कहा कि नि-क्षय पोषण योजना के अंतर्गत वर्ष 2025 के दौरान 1,05,238 टीबी मरीजों को 57.60 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जनप्रतिनिधि, पंचायती राज संस्थाएं, कॉर्पोरेट क्षेत्र तथा स्वैच्छिक संस्थाएं निक्षय मित्र के रूप में जुड़ी हैं। राज्य में अब तक 30,992 नि-क्षय मित्र पंजीकृत हुए हैं, जिन्होंने मरीजों को 5,50,184 पोषण किटों का वितरण किया है।

वर्ष 2025 के दौरान राज्य की 3,971 ग्राम पंचायतों ने 'टीबी मुक्त पंचायत' का दर्जा प्राप्त किया, जो राज्य की कुल ग्राम पंचायतों का लगभग 27 प्रतिशत है।

‘पहला सुख निरोगी काया’ और ‘प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर’ के संदेश को जीवन में उतारने की आवश्यकता है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ मुख्यमंत्री का स्वच्छता को सबका साझा संकल्प तथा समाज का सहज स्वभाव बनाने का आह्वान
▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर से ‘नमो स्वच्छता अभियान’ तथा अमृतपान अभियान का राज्यव्यापी शुभारंभ कराया
▸▸ 1 से 7 जुलाई तक राज्य की सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में सघन स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा
▸▸ स्वच्छता अब अस्पतालों की दैनिक प्रक्रिया बनेगी : स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रफुल पानशेरिया

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को गांधीनगर से ‘नमो स्वच्छता अभियान’ और ‘अमृतपान अभियान’ का राज्यव्यापी शुभारंभ कर स्वच्छता को सबका साझा संकल्प और जन-जन का सहज स्वभाव बनाने का आह्वान किया।

उन्होंने जोड़ा कि स्वच्छता केवल एक सप्ताह तक सीमित रहने वाली गतिविधि नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव और दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बननी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘पहला सुख निरोगी काया’ और ‘प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर’ के संदेश को जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और स्वास्थ्य एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं तथा गंदगी न फैलाने और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने की सामूहिक जिम्मेदारी निभाने के लिए सभी को प्रेरणा दी।

श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘स्वच्छ भारत अभियान’, ‘हर घर जल’ ‘उज्जवला योजना’, ‘आयुष्मान भारत’ सहित अनेक पहलों से देश के नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ स्वच्छता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के प्रभावी प्रयास किए हैं। मुख्यमंत्री ने जोड़ा कि सुदूरवर्ती व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए सरकार सतत प्रयत्नशील है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘नमो स्वच्छता अभियान’ अंतर्गत 1 से 7 जुलाई यानी सात दिनों के दौरान अस्पतालों तथा स्वास्थ्य संस्थाओं में पुराना फर्नीचर, आउटडेटेड मेडिकल ससांधन तथा अनावश्यक दस्तावेजों का उचित निपटान कर पूरे परिसर को स्वच्छ बनाने का कार्य किया जाएगा । उन्होंने उदाहरणों के साथ कहा कि यह अभियान केवल एक साप्ताहिक अभियान न रहकर दैनिक स्वच्छता का अभियान बने, इसके लिए सभी को जिम्मेदारी निभानी होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘अमृतपान अभियान’ बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जन्म के समय से ही बच्चे को उचित पोषण और सुरक्षा मिले, इसके लिए व्यापक जनजागरूकता लाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ बच्चा ही स्वस्थ समाज और विकसित राष्ट्र की मजबूत नींव बन सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भौतिक सुख सुविधाओं की अपेक्षा अच्छा स्वास्थ्य अधिक मूल्यवान है। बीमारी के समय अनुभव होने वाला तनाव स्वास्थ्य के वास्तविक महत्व को समझाता है। उन्होंने आयुष्मान कार्ड को गरीब परिवारों के लिए आशीर्वाद बताते हुए कहा कि गुजरात में ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाओं का उल्लेखनीय विकास हुआ है।

उन्होंने आगे कहा कि स्वास्थ्य सेवा केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि मानव सेवा का सर्वोत्तम माध्यम है तथा गरीब और जरूरतमंद मरीजों के आशीर्वाद से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती।

मुख्यमंत्री ने अस्पतालजनित संक्रमण की दर कम करने के लिए संक्रमण नियंत्रण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल देते हुए सभी स्वास्थ्य कर्मियों और नागरिकों से स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित गुजरात के निर्माण में सामूहिक प्रयासों से जुड़ने की प्रेरणा दी।

राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी डॉक्टरों को शुभकामनाएं दीं तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना की।

‘राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस’ पर सभी डॉक्टरों को शुभकामनाएं देते हुए स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रफुल पानशेरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक ऐतिहासिक और व्यापक ‘नमो स्वच्छता अभियान’ का राज्यव्यापी शुभारंभ किया गया है। यह अभियान केवल एक दिन या कुछ घंटों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगामी सात दिनों तक लगातार चलेगा और उसके बाद इसे अस्पतालों की दैनिक कार्यप्रणाली का हिस्सा बनाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इस अभियान अंतर्गत अस्पताल परिसर और कमरों में लंबे समय से पड़ी टूटी-फूटी कुर्सियां, अनुपयोगी कंप्यूटर, पुराने टेम्पो और कबाड़ हो चुकी एम्बुलेंसों का सात दिनों में पूर्ण निपटान किया जाएगा तथा उस स्थान का उपयोग मरीजों की सुविधा के लिए किया जाएगा। सभी सिविल अस्पतालों तथा पीएचसी तथा सीएचसी केंद्रों में टूटी टाइलें, दरवाजे, खिड़कियां, लाइट-पंखों की फिटिंग तथा शौचालयों में लीकेज वाले नलों की मरम्मत युद्ध स्तर पर की जाएगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सफल नेतृत्व में 12 वर्षों की उपलब्धि में यह स्वच्छता अभियान उन्हें समर्पित एक श्रेष्ठ भेंट के समान है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रफुल पानशेरिया ने विश्वास व्यक्त किया कि ‘मन स्वच्छ, शरीर स्वच्छ, मेरा स्वास्थ्य भवन स्वच्छ’ के मंत्र के साथ गुजरात का स्वास्थ्य विभाग देशभर में अपना अग्रणी स्थान बनाए रखेगा।

इस राज्यव्यापी महाअभियान दौरान राज्य की सभी 11,935 सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में परिसर से लेकर बरामदा तथा छत तक सघन स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री राजीव टोपनो ने स्वागत भाषण दिया, जबकि स्वास्थ्य आयुक्त (शहरी) डॉ. संध्या भुल्लर ने आभार विधि की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रफुल पानशेरिया सहित उपस्थित महानुभावों के करकमलों से ‘अमृतपान अभियान मार्गदर्शिका’ और ‘फ्लिप चार्ट’ का अनावरण किया गया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा राज्य की सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में स्वच्छता और सुव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रफुल पानशेरिया ने गांधीनगर सिविल परिसर में स्वयं सफाई कर ‘नमो स्वच्छता अभियान’ का राज्यव्यापी शुभारंभ कराया।

इस अवसर पर गांधीनगर महानगर पालिका की महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, जिला पंचायत प्रमुख श्री राजेशकुमार पटेल, ग्रामीण स्वास्थ्य आयुक्त डॉ. रतनकंवर गढ़वी चारण, कलेक्टर श्री रविंद्र खताले, जिला विकास अधिकारी डॉ. हसरत जैस्मीन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तथा जीएमईआरएस मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी उपस्थित रहे।

वडोदरा स्टेशन पर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली का शुभारंभ,वडोदरा यार्ड री-मॉडलिंग कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल ने मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके के कुशल नेतृत्व में रेल परिचालन के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए वडोदरा स्टेशन पर व्यापक सिग्नलिंग अपग्रडेशन तथा यार्ड री-मॉडलिंग कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। लगभग 34 वर्ष पुरानी सीमेंस निर्मित रूट रिले इंटरलॉकिंग यानि RRI प्रणाली को हटाकर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग यानि EI प्रणाली स्थापित की गई, जिसका सफल कमीशनिंग 01 जुलाई 2026 को किया गया। यार्ड री-मॉडलिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का यह कार्य वडोदरा स्टेशन की परिचालन क्षमता, संरक्षा, विश्वसनीयता तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्रियान्वित किया गया है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना का कार्य स्वीकृत 70 दिवसीय ट्रैफिक वर्किंग ऑर्डर (TWO) के अंतर्गत चरणबद्ध रूप से सम्पन्न किया जा रहा है। 16 मई से 29 जून 2026 तक 45 दिनों की प्री-ट्रैफिक वर्किंग अवधि में कुल 209 घंटे 55 मिनट के एकीकृत ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक लेकर विभिन्न आधारभूत कार्य पूरे किए गए। इसके पश्चात 30 जून से 01 जुलाई 2026 तक निर्धारित नॉन-इंटरलॉकिंग (NI) कार्य मात्र 23 घंटे 55 मिनट में सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया, जबकि इसके लिए 24 घंटे का समय निर्धारित था। इस अवधि में केवल 5 घंटे 46 मिनट का ट्रैफिक ब्लॉक लेकर 147 ट्रेनों (70 अप एवं 77 डाउन) का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित किया गया।

यार्ड री-मॉडलिंग के अंतर्गत परिचालन में बाधा उत्पन्न करने वाली डबल स्लिप डायमंड क्रॉसिंग को हटाकर यार्ड का ट्रैक विन्यास आधुनिक बनाया जा रहा है। डबल स्लिप डायमंड क्रॉसिंग के कारण लागू 10 किमी/घंटा की स्थायी गति सीमा (Permanent Speed Restriction) हटाकर लाइन संख्या 6 एवं 7 पर अनुमेय गति 30 किमी/घंटा कर दी गई है। इससे यार्ड में ट्रेनों की आवाजाही अधिक सुगम, तेज एवं सुरक्षित होगी। डाउन दिशा से आने वाली ट्रेनों का प्लेटफॉर्म संख्या 6 एवं 7 पर शीघ्र प्रवेश संभव होगा, जिससे ट्रेन डिटेंशन में कमी आएगी तथा परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय सुधार होगा। इसके साथ ही स्टेशन पर नया स्टेशन मास्टर कार्यालय, उपकरण कक्ष एवं स्टोर भी स्थापित किए गए हैं।

वडोदरा स्टेशन पर यार्ड री-मॉडलिंग के तहत वडोदरा यार्ड में 10 पॉइंट्स एवं क्रॉसिंग (P&C) हटाए गए, 12 स्थानों पर ट्रैक लेआउट में सुधार किया गया तथा 13 नए पॉइंट्स एवं क्रॉसिंग स्थापित किए गए। लगभग 1.5 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाकर लाइन संख्या 6 एवं 7 को डाउन मेन लाइन तथा सी केबिन को अप गुड्स मेन लाइन से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त 10 WCMS, 22 टर्नआउट का नवीनीकरण (TTR/TSR), 15 थिक वेब स्विच (TWS) की स्थापना तथा 22 पॉइंट्स एवं क्रॉसिंग एवं 1.5 किलोमीटर ट्रैक की डीप स्क्रीनिंग का कार्य भी सम्पन्न किया गया।

सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के अंतर्गत वर्ष 1992 में स्थापित 228 रूटों वाली RRI प्रणाली को प्रतिस्थापित कर 189 रूट एवं 10 स्लॉट वाली अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (EI) प्रणाली स्थापित की गई है। नई प्रणाली में 65 डीसी ट्रैक सर्किटों के स्थान पर 66 ड्यूल MSDAC इकाइयों की स्थापना की

राज्य में मेहसाणा जिला पंचायत की सर्वप्रथम नूतन पहल : ‘जिला पंचायत आपके द्वार’ कार्यक्रम का शक्तिपीठ बहुचराजी से शुभारंभ

▸▸ जनता की समस्याओं के मौके पर ही समाधान के लिए प्रशासन सक्रिय; सड़क-मार्ग, पानी और पंचायत से जुड़े लंबित मुद्दों पर लिए गए त्वरित निर्णय
▸▸ प्रशासनिक प्रक्रिया को वेग देने के लिए तहसील स्तर पर मस्टर मैंटेन कर हर महीने रिव्यू लिया जाएगा : जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नितिनभाई पटेल

गांधीनगर : ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को अपनी लंबित तथा जनहित से जुड़ी समस्याओं की प्रस्तुति के लिए जिला मुख्यालय तक न आना पड़े; इस उद्देश्य से मेहसाणा जिला पंचायत द्वारा राज्य में पहली बार ‘जिला पंचायत आपके द्वार’ कार्यक्रम की नूतन पहल की गई है। मेहसाणा जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री नितिनभाई पटेल के मार्गदर्शन में इस अभियान का शुभारंभ बुधवार को सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ बहुचराजी से किया गया।

इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन सीधे ही जनता के द्वार पहुँचा, जिसमें पहली बार आवेदकों को खुले मन से अपनी मूलभूत समस्याएँ प्रस्तुत करने के लिए एक सटीक मंच प्रदान किया गया। बहुचराजी के अन्नपूर्णा भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में बहुचराजी तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों ने बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर सड़क-मार्ग, पेयजल, बोरवेल, ग्राम पंचायत में पटवारी की उपस्थिति तथा नवीन ग्राम पंचायत भवन जैसे मूलभूत विषयों से संबंधित समस्याएँ प्रस्तुत कीं। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नितिनभाई पटेल ने प्रत्येक प्रस्तुति को अत्यंत गंभीरता से सुना तथा स्थल पर उपस्थित सम्बद्ध विभागों के अधिकारियों से इन समस्याओं के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का समयसीमा में समाधान किया जाए तथा नागरिकों को अनावश्यक परेशानी न हो; इसका ध्यान रखा जाए।

इस कार्यक्रम के दौरान जनहित से जुड़े विभिन्न कार्यों पर विस्तृत चर्चाएँ हुईं, जिसमें शंखलपुरे-कालरी बाईपास पर नहर के कारण रुके हुए 200 मीटर सड़क निर्माण कार्य को पूरा करने, डोडीवाडा-आदीवाडा से खांभेल चौकडी तक की क्षतिग्रस्त सड़क को नई एवं चौड़ी बनाने और कनोडा-रणेला सड़क के अधूरे कार्य को शीघ्र पूरा करने संबंधी प्रस्तुतियाँ की गईं। इसके अतिरिक्त; रणेला ग्राम पंचायत में स्थायी पटवारी की नियुक्ति करने, नया पंचायत घर बनाने तथा आकबा-बरियफ रोड का नया निर्माण कराने जैसी मांगों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

ग्रामीणों द्वारा सदुथला गाँव में पेयजल के लिए नया बोरवेल बनाने तथा रातेज-राजपुरा-देथली रेलवे अंडरपास के कारण लंबे समय से बंद पड़ी एसटी बस सेवा को पुनः प्रारंभ कराने के लिए भी प्रबल प्रस्तुति की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नितिनभाई पटेल ने इस अवसर पर कहा कि प्रशासनिक सेवाएँ अंतिम छोर पर बसे व्यक्ति तक सरलता से पहुँचें तथा स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो; यही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक तहसील में चिटनीश द्वारा एक अलग मास्टर लागू किया जाएगा, जिसमें प्रस्तुत की गई समस्याओं का पंजीकरण कर उनका फॉलो-अप लिया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा हर महीने इन समस्याओं की समीक्षा की जाएगी तथा जो विषय राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र से संबंधित होंगे, उन्हें उच्च स्तर पर प्रस्तुत कर शीघ्र समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

कार्यक्रम के प्रारंभ में बहुचराजी के टीडीओ श्री जे. जे. चौधरी ने इस नूतन पहल की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए सभी को इसकी जानकारी दी। लोक दरबार के साथ-साथ इस अवसर पर सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रमाणपत्रों का भी वितरण किया गया, जिसमें आयुष्मान कार्ड, आय प्रमाणपत्र तथा जाति प्रमाणपत्र के लाभार्थियों को अधिकारियों के करकमलों से प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

गुजरात में आगामी 7 जुलाई से ग्रीष्मकालीन मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू होगी : प्रवक्ता मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी

▸▸ बिक्री के लिए 14,383 किसानों ने पंजीकरण कराया; खरीद के लिए 51 खरीद केन्द्र सुनिश्चित किए गए
▸▸ बुवाई क्षेत्र के अनुपात में प्रति किसान अधिकतम 1,500 किलोग्राम (75 मन) मूंग की खरीद की जाएगी

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में बुधवार को गांधीनगर में आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसकी जानकारी देते हुए प्रवक्ता मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने बताया कि गुजरात में आगामी 7 जुलाई से ग्रीष्मकालीन मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू होगी।

उन्होंने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए ग्रीष्मकालीन मूंग का समर्थन मूल्य 8,768 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। जब भी बाजार मूल्य समर्थन मूल्य से नीचे चला जाता है, तब किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए भारत सरकार की ‘पीएम आशा’ योजना अंतर्गत पीएसएस के तहत राज्य में ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल की समर्थन मूल्य पर खरीद की जाती है।

प्रवक्ता मंत्री ने कहा कि ग्रीष्मकालीन मूंग को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए राज्यभर से कुल 14,383 किसानों ने पंजीकरण कराया है। पंजीकृत किसानों से खरीद करने के लिए राज्य में कुल 51 खरीद केन्द्र सुनिश्चित किए गए हैं।

पंजीकरण कराने वाले किसानों को खरीद संबंधी सूचना एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। किसानों को एसएमएस प्राप्त होने के बाद उन्हें आवंटित खरीद केन्द्र पर मूंग की निर्धारित मात्रा के साथ उपस्थित रहना होगा।

वर्ष 2025-26 में ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद 1,200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के आधार पर किसान के बुवाई क्षेत्र के अनुपात में की जाएगी, जिसमें प्रति किसान अधिकतम 1,500 किलोग्राम (75 मन) तक की सीमा निर्धारित रहेगी।

उन्होंने राज्य के सभी पंजीकृत किसानों से राज्य सरकार की ओर से अनुरोध किया है कि वे समय पर इस योजना का अधिकतम लाभ प्राप्त करें।

जीएसटी कलेक्शन ने रचा नया इतिहास, जून में पहली बार 1.95 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंची वसूली

देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू होने के नौ वर्ष पूरे होने के बीच कर संग्रह ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। जून 2026 में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,812 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो अब तक जून महीने का सर्वाधिक संग्रह माना जा रहा है। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में इसमें 13.9 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्र सरकार का मानना है कि लगातार बढ़ता कर संग्रह देश में मजबूत आर्थिक गतिविधियों, बेहतर कर अनुपालन, डिजिटल कर व्यवस्था की सफलता और औपचारिक अर्थव्यवस्था के विस्तार का संकेत देता है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून 2025 में सकल जीएसटी संग्रह 1,71,105 करोड़ रुपये था। इसके मुकाबले इस वर्ष जून में कर संग्रह में करीब 24 हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब जीएसटी प्रणाली अपने नौ वर्ष पूरे कर चुकी है और सरकार लगातार कर आधार को व्यापक बनाने तथा कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए तकनीकी सुधारों पर जोर दे रही है।

चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही भी कर संग्रह के लिहाज से उत्साहजनक रही। अप्रैल से जून 2026 के दौरान कुल सकल जीएसटी संग्रह 6,31,699 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 5,82,542 करोड़ रुपये था। इस प्रकार पहली तिमाही में जीएसटी संग्रह में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। लगातार तीन महीनों तक मजबूत कर संग्रह से सरकार को वित्तीय प्रबंधन और विकास योजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होने की उम्मीद है।

वित्त मंत्रालय के अनुसार घरेलू कारोबार से प्राप्त सकल जीएसटी राजस्व भी जून महीने में बढ़ोतरी के साथ 1,34,774 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। पिछले वर्ष जून में यह आंकड़ा 1,26,506 करोड़ रुपये था। इससे संकेत मिलता है कि घरेलू बाजार में व्यापारिक गतिविधियां और उपभोग दोनों मजबूत बने हुए हैं। उद्योग, सेवा क्षेत्र और खुदरा कारोबार में निरंतर गतिविधियों का असर कर संग्रह पर भी सकारात्मक रूप से दिखाई दिया है।

जून महीने में आयातित वस्तुओं से प्राप्त जीएसटी राजस्व में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार आयात से होने वाला कर संग्रह 34.6 प्रतिशत की तेज वृद्धि के साथ 60,038 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष जून में यह 44,600 करोड़ रुपये था। विशेषज्ञों का मानना है कि आयात में बढ़ोतरी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार गतिविधियों और उच्च मूल्य वाले आयातित उत्पादों से सरकार को अधिक कर राजस्व प्राप्त हुआ है।

रिफंड समायोजन के बाद शुद्ध जीएसटी संग्रह भी मजबूत बना रहा। जून 2026 में शुद्ध कर संग्रह 11.2 प्रतिशत बढ़कर 1,62,377 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। वहीं कारोबारियों को जारी किए गए जीएसटी रिफंड में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली। इस महीने कुल 32,436 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 29.1 प्रतिशत अधिक है। समय पर रिफंड जारी होने से निर्यातकों और उद्योग जगत को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने में सहायता मिलती है तथा व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलती है।

एक जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू की गई जीएसटी व्यवस्था को भारत के सबसे बड़े कर सुधारों में गिना जाता है। इस प्रणाली ने केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले अनेक अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत कर ‘एक राष्ट्र, एक कर’ की अवधारणा को लागू किया। इसके बाद से कर प्रणाली अधिक पारदर्शी बनी है, डिजिटल अनुपालन को बढ़ावा मिला है और करदाताओं की संख्या में भी लगातार वृद्धि हुई है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि लगातार बढ़ता जीएसटी संग्रह केवल कर प्रशासन की दक्षता का परिणाम नहीं है, बल्कि यह अर्थव्यवस्था में बढ़ते लेनदेन, बेहतर अनुपालन, ई-इनवॉइसिंग, डेटा विश्लेषण आधारित निगरानी और कर चोरी पर सख्त नियंत्रण का भी संकेत है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के व्यापक उपयोग से कर संग्रह प्रणाली पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी और प्रभावी हुई है।

सरकार का कहना है कि जीएसटी व्यवस्था में लगातार सुधार किए जा रहे हैं ताकि करदाताओं के लिए अनुपालन आसान बनाया जा सके और राजस्व संग्रह को और मजबूत किया जा सके। आने वाले समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी, डेटा इंटीग्रेशन और तकनीकी सुधारों के माध्यम से कर प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम जारी रहेगा।

लगातार बढ़ता जीएसटी संग्रह केंद्र और राज्यों दोनों के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

देशभर में मानसून का व्यापक असर: दिल्ली सहित 20 से अधिक राज्यों में अगले कई दिनों तक बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट

नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिम मानसून अब पूरे देश में सक्रिय हो चुका है और आने वाले दिनों में इसका प्रभाव और अधिक व्यापक होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने राजधानी दिल्ली सहित उत्तर, मध्य, पूर्व और पर्वतीय क्षेत्रों के 20 से अधिक राज्यों के लिए अगले कई दिनों तक बारिश, तेज आंधी, बिजली गिरने और कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगातार मिल रही नमी तथा सक्रिय मानसूनी ट्रफ के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज बनी रहेंगी। कई राज्यों में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है, जिससे जहां किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं निचले इलाकों में जलभराव, भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले पांच दिनों तक मौसम सुहावना लेकिन चुनौतीपूर्ण बना रहेगा। आईएमडी ने राजधानी के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और बीच-बीच में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश भी दर्ज की जा सकती है। अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। बारिश के कारण उमस में कमी आएगी, लेकिन जलभराव और यातायात बाधित होने जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 6 जुलाई तक राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में मौसम का यही रुख बना रह सकता है।

उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में 1 से 6 जुलाई तक लगातार बारिश होने की संभावना जताई गई है। इन राज्यों में कई स्थानों पर तेज हवाएं, आंधी, गरज-चमक और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। मौसम विभाग ने विशेष रूप से 2 से 6 जुलाई के बीच भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को खुले स्थानों पर जाने से बचने और बिजली गिरने के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।

राजस्थान में भी मानसून धीरे-धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। पूर्वी राजस्थान में 1 जुलाई से वर्षा की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर और आसपास के जिलों में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान, जहां सामान्यतः कम वर्षा होती है, वहां भी 3 से 6 जुलाई के बीच बारिश और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जैसे क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में दृश्यता कम होने और सड़क परिवहन प्रभावित होने की आशंका भी जताई है।

उत्तर प्रदेश में भी मौसम तेजी से बदलने वाला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से लगातार वर्षा की संभावना है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3 जुलाई से बारिश का दायरा और बढ़ जाएगा। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, आगरा और बरेली सहित अनेक जिलों में गरज-चमक के साथ वर्षा होने का अनुमान है। कई स्थानों पर बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। खेतों में कार्य कर रहे किसानों को भी मौसम की जानकारी लेकर ही बाहर निकलने की सलाह दी गई है।

पर्वतीय राज्यों में मानसून सबसे अधिक सक्रिय दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में अगले कई दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में विशेष रूप से 2 से 4 जुलाई के बीच अत्यधिक भारी वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया गया है। शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा और सिरमौर जैसे जिलों में भूस्खलन, सड़क अवरुद्ध होने और नदियों-नालों के उफान पर आने की आशंका है। उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और टिहरी क्षेत्रों में भी लगातार बारिश जारी रहने की संभावना है। चारधाम यात्रा मार्गों पर यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को मौसम की जानकारी लेकर ही आगे बढ़ने की सलाह दी गई है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कुछ क्षेत्रों में भी गरज-चमक के साथ तेज वर्षा तथा तेज हवाएं चल सकती हैं। पर्वतीय इलाकों में हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक के तेज झोंके चलने की संभावना है। ऐसे मौसम में पहाड़ी मार्गों पर यात्रा करने वालों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी।

मध्य भारत में भी मानसून का असर लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र में अगले कई दिनों तक मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर सहित अनेक शहरों में गरज-चमक के साथ बारिश दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कई स्थानों पर बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। इससे किसानों और खुले क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

पूर्वी भारत के राज्यों में भी मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार में अगले कई दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। झारखंड में 6 जुलाई तक लगातार वर्षा की संभावना है, जबकि बिहार में 2 से 6 जुलाई के बीच अधिकांश जिलों में हल्की से भारी बारिश हो सकती है। पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, रांची, धनबाद, कोलकाता, पुरुलिया, भुवनेश्वर और कटक जैसे क्षेत्रों में कई दौर की बारिश दर्ज होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं।

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी समुद्री गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। यहां लगातार वर्षा और तेज हवाओं की संभावना के मद्देनजर मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। समुद्री लहरें ऊंची उठने और मौसम खराब रहने की आशंका को देखते हुए स्थानीय प्रशासन सतर्क है।

मौसम विभाग का कहना है कि सक्रिय मानसून के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में कृषि गतिविधियों को लाभ मिलेगा। खरीफ फसलों की बुवाई में तेजी आने की संभावना है और जलाशयों का जलस्तर भी बढ़ेगा। हालांकि अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़, जलभराव, भूस्खलन और नदी-नालों के उफान जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। इसलिए स्थानीय प्रशासन को पहले से ही आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं।

आईएमडी ने नागरिकों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, बिजली कड़कने के समय खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें तथा मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा करने वाले पर्यटक और श्रद्धालु भी मौसम की ताजा जानकारी लेकर ही सफर करें।

विशेषज्ञों का मानना है कि जुलाई का पहला सप्ताह देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून के लिए अत्यंत सक्रिय रहने वाला है। यदि वर्तमान परिस्थितियां बनी रहती हैं तो उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और पहाड़ी राज्यों में अच्छी वर्षा दर्ज होगी। हालांकि इसके साथ ही अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सतर्कता बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक होगा, ताकि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।